

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 गहलोट के जाने के बाद इस भाजपा विधायक ने ज्वाइन की पार्टी

06 डिजिटल मीडिया नैतिकता

08 सनातन सभ्यता, गौसेवा और समाज सेवा के प्रतीक

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-4 लागू, ट्रकों की एंटी बैन, दफ्तरों को डब्ल्यूएफएच का निर्देश; जानिए क्या-क्या हैं पाबंदियां

संजय बाटला

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-4 चरण लागू हो गया। इस वजह से राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर के शहरों में प्रतिबंध लगाए गए हैं। ग्रेप के तहत चरण पहले ही लागू हो चुके हैं। क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है और एक्वआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। सीएक्यूएम ने दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में ग्रेड-4 रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप, GRAP) का चौथा चरण लागू हो गया। इस वजह से राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर के शहरों में प्रतिबंध लगाए गए हैं। ग्रेप के तहत चरण पहले ही लागू हो चुके हैं। क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है और एक्वआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम, CAQM) के अनुसार, ग्रेप का चौथा चरण 18 नवंबर (सोमवार) सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा।

ग्रेप-4 के तहत लगाए गए प्रतिबंध

दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक (आवश्यक सेवाओं के लिए ट्रकों का जारी रहेगा प्रवेश)

LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और बीएस-4 डीजल ट्रकों के प्रवेश पर रोक नहीं रहेगी।

इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, बीएस-4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। (अनुमति सिर्फ जरूरी सेवा देने वालों के लिए होगी)

दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 और उससे कम के डीजल मालवाहक और भारी वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा।



हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी परियोजनाओं के कामों (निर्माण कार्य) पर प्रतिबंध ग्रेप-3 के तहत लागू रहेगा।

दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारें सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति दें।

राज्य सरकारों को दीये सलाह

एनसीआर के शहरों और दिल्ली में सरकारें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को कक्षा-11 तक की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित करने का निर्णय ले सकती हैं।

केंद्र सरकार केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने पर उचित निर्णय ले सकती है।

राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, जैसे कॉलेज/शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करना, पंजीकरण संख्या के आधार पर वाहनों

को सम-विषम (ऑड-ईवन) आधार पर चलाने की अनुमति देना आदि।

दिल्ली का एक्वआई

दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता और भी खराब हो गई। एक्वआई 441 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में है। इससे यह देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। दिल्ली से सटे और हरियाणा के जिले बहादुरगढ़ का एक्वआई सबसे ज्यादा 445 दर्ज हुआ।

AQI से वायु प्रदूषण का चलता है पता

वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) एक नंबर होता है जिसके जरिए हवा की गुणवत्ता को आंका जाता है। इससे वायु में मौजूद प्रदूषण के स्तर का भी पता लगाया जाता है। एक्वआई की रीडिंग के आधार पर हवा की गुणवत्ता को छह कैटेगरी में बांटा गया है। शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 और 100 संतोषजनक, 101 और 200 मध्यम, 201 और 300 खराब, 301 और 400 बहुत खराब, और 401 और 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसन्न क्षेत्र
राज्य गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
Commission for Air Quality Management in
National Capital Region and
Adjoining Areas

No.120017/27/GRAP/2021/CAQM Dated: 17.11.2024

ORDER

Sub: Implementation of Actions under stage-IV ('Severe' Air Quality) of revised Graded Response Action Plan in Delhi-NCR- steps to be taken.

The Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas, vide Direction No. 83 dated 17th September, 2024, issued statutory direction for implementation of the revised schedule of the Graded Response Action Plan (GRAP), available on the CAQM website (caqm.nic.in), as and when orders under GRAP are invoked.

The Sub-Committee for invoking actions under the GRAP in its earlier meetings held, had invoked actions under Stage-I, Stage-II and Stage-III of the GRAP on 14th October, 2024, 21st October, 2024 and 14th November, 2024.

The Sub-Committee in its urgent meeting held on 17th November, 2024 further reviewed the air quality scenario in the region as well as the forecasts for meteorological conditions and air quality index of Delhi made available by IMD/IITM.

The Sub-Committee observed that the AQI of Delhi was recorded at 441 (Severe) at 4:00 P.M on 17.11.2024 (today) and has been gradually increasing further and has already reached 'Severe+' category, as the AQI clocked 447, 452 and 457 at 5:00 P.M, 6:00 P.M and 7:00 P.M respectively. Further, the average AQI for Delhi is expected to remain in this adverse range owing to heavy fog, variable winds, highly unfavorable meteorological and climatic conditions. Forecasts from IMD/IITM also indicate a likelihood of the AQI of Delhi to particularly remain in higher end of 'SEVERE'/'SEVERE+' category in the coming days, owing to unfavorable climatic conditions.

Therefore, in an effort to prevent further deterioration of the air quality, the Sub-Committee decided that **ALL actions as envisaged under Stage IV of the GRAP - 'Severe+' Air Quality (DELHI AQI=50)** be implemented in right earnest by all the agencies concerned in the NCR, in addition to the Stage-I, II and III actions already in force, from 8:00 A.M. of 18.11.2024 in the National Capital Region (NCR).

1 | Page 10

- These include:
- Stop entry of truck traffic into Delhi (except for trucks carrying essential commodities/ providing essential services). All LNG / CNG / Electric/ BS-VI Diesel trucks shall, however, be permitted to enter Delhi.
 - Do not permit LCVs registered outside Delhi, other than EVs / CNG / BS-VI diesel, to enter Delhi, except those carrying essential commodities / providing essential services.
 - Enforce strict ban on plying of Delhi - registered BS-IV and below diesel operated Medium Goods Vehicles (MGVs) and Heavy Goods Vehicles (HGVs) in Delhi, except those carrying essential commodities / providing essential services.
 - Ban C&D activities, as in the GRAP Stage-III, also for linear public projects such as highways, roads, flyovers, overbridges, power transmission pipelines, tele-communication etc.
 - NCR State Govts. and GNCTD may take a decision on discontinuing physical classes even for classes VI - IX, class XI and conduct lessons in an online mode.
 - NCR State Governments / GNCTD to take a decision on allowing public, municipal and private offices to work on 50% strength and the rest to work from home.
 - Central Government may take appropriate decision on permitting work from home for employees in central government offices.
 - State Governments may consider additional emergency measures like closure of colleges/ educational institutions and closure of non-emergency commercial activities, permitting running of vehicles on odd-even basis of registration numbers etc.
- Further, citizens may be urged to adhere to the citizen charter and assist in effective implementation of the GRAP measures aimed towards sustaining and improving the Air Quality in the Region, in addition to the citizen charter of Stage-I, Stage-II and Stage-III, as under:
- Children, elderly and those with respiratory, cardiovascular, cerebrovascular or other chronic diseases to avoid outdoor activities and stay indoors, as much as possible.
- 17/11/24
R.K. Aggarwal
Director (Technical)
(Member Convener of Sub-Committee on GRAP)
- 2 | Page 10

परिवहन विभाग का राजा गार्डन क्षेत्रीय कार्यालय भी हुआ बन्द

संजय बाटला

नई दिल्ली। हमने आप सभी को पिछले महीने ही सूचना दे दी थी कि परिवहन आयुक्त किसी भी समय राजा गार्डन क्षेत्रीय शाखा को बंद कर द्वारका क्षेत्रीय शाखा में विलय के आदेश जारी कर सकता है और आदेश जारी हो गया।

पहले जनकपुरी क्षेत्रीय शाखा को जनहित में दो हिस्सों में बाटा गया था की जनता अपने घर के करीब परिवहन सम्बन्धी अपने कार्य करवा सके। फिर जनहित को दर्शाना कर राजस्व के इजाफे को मद्देनजर रखते हुए जनकपुरी क्षेत्रीय शाखा को बंद कर उसका विलय राजा गार्डन में किया गया था और अब अधिक सरकारी राजस्व इजाफे के तहत राजा गार्डन क्षेत्रीय शाखा को ताला लगाकर द्वारका क्षेत्रीय शाखा में विलय के आदेश जारी कर दिए।

द्वारका क्षेत्रीय शाखा में अब चार (4) क्षेत्रीय कार्यालयों में हो रहे परिवहन से संबंधित कार्यों को करेगा। अर्थात चारों क्षेत्रीय शाखाओं में पंजीकृत वाहनों से संबंधित सभी कार्य, ट्रेड सर्टिफिकेट नवीनीकरण एवम्नए, ड्राइविंग एवम्कंडक्टर लाइसेंस नवीनीकरण, ड्राइवर एवम्कंडक्टर बेज नवीनीकरण और इंटरनेशनल लाइसेंस जारी करने, इत्यादि कार्यों के लिए जनता जनार्दन को द्वारका क्षेत्रीय शाखा में जाना होगा।



OFFICE OF THE DISTRICT TRANSPORT OFFICER (SWZ)
TRANSPORT DEPARTMENT, GOVT. OF NCT OF DELHI
(ADMINISTRATIVE BRANCH)
5/9 UNDER HILL ROAD DELHI - 110054

F.No. F9/246/OTO/SWZ/2024/CD-07594828/62.4+5 Dated:- 16/11/2024

ORDER

Sub - Merger of National Transport Office Raja Garden into Dwarka Zonal Office located at Dwarka Sector -16, New Delhi-110075.

In the interest of enhancing operational efficiency, optimizing resource utilization, and improving public service delivery, it has been decided to merge the Zonal transport Office located at Raja Garden into Dwarka Zonal Office located at Dwarka Sector-10.

All administrative, operational, and public-facing functions currently being carried out at Raja Garden Zonal Transport Office (Janak Puri, DL-94) & Raja Garden (DL-10) shall be transferred to the Dwarka Zonal Transport Office, Sector-10, with effect from 18/11/2024.

DTO (Dwarka) will handle the merged entity. All staff/Computers and other vital record (other than record room) to be shifted to Dwarka Zonal Office sector-10 upto 17/11/2024.

Automated Driving test track (ADTT) at Raja Garden and Hari Nagar to continue to work under concerned MVI/Foreman, who shall report to DTO Dwarka. DTO Office at Raja Garden to be locked under watch of a guard and clear board depicting that for office work the applicant may contact to DTO Dwarka at the following address:

"Office of the District Transport Officer, Transport Department, GNCT of Delhi, Sector-10, Dwarka (Near Metro Station Dwarka Sector-10), New Delhi - 110075"

This issue with the prior approval of Additional Chief Secretary cum Commissioner, Transport Department, GNCT of Delhi.

Copy for information to :-

1. PA to Additional Chief Secretary cum Commissioner, Transport Department, GNCTD.
2. PA to All Spt. Commissioner, Transport Department, GNCTD.
3. All Deputy Commissioner, Transport Department, GNCTD
4. All DTOs, Transport Department, GNCTD
5. Sr. System Analyst, Transport Department, GNCTD for uploading on Transport Department website and update address on all types of Fees Receipts and applications on Vahan-4 and Sarathi portal.

16/11/24
Dy. Commissioner (Admin)

नजफगढ़ वालों के लिए अच्छी खबर ! रावता मोड़ तक होगा मेट्रो की ग्रे लाइन का विस्तार

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली मेट्रो की ग्रे लाइन का विस्तार बार्डर से बढ़ाकर जल्द ही रावता मोड़ तक किया जाएगा। इस विस्तार से मित्राऊं सुरहेड़ा गांव डाबर एक्लेव कॉलोनी गोपाल नगर कॉलोनी जाफरपुर गांव के निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही कई शैक्षिक संस्थान रावता मोड़ पर ही हैं तो इससे हजारों छात्रों और शिक्षण संकाय को अपने कॉलेज तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली। दिल्ली से नजफगढ़ आवागमन करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली मेट्रो की ग्रेलाइन का डांबरा बार्डर से बढ़ाकर जल्द ही रावता मोड़ तक विस्तार किया जाएगा। ग्रेलाइन अभी डांबरा से डांबरा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन तक ही है। इसमें अब मित्राऊं और सुरहेड़ा से होते हुए रावता मोड़ तक मेट्रो का विस्तार होगा, यानी तीन नए स्टेशन बनाए जाएंगे। मेट्रो का 6.89 किमी लंबा विस्तार होगा।

किसिमिलेगाफायदा ?

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोट ने अपने एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मेट्रो के इस विस्तार से आसपास की कॉलोनीयों और गांवों के निवासियों को यात्रा में बहुत आसानी होगी। कैलाश गहलोट ने अनुसार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) द्वारा विभाग को मार्ग का व्यवहारांतरा परीक्षण और विस्तार परियोजना रिपोर्ट जमा कर दी गई है। इसके बाद कैलाश गहलोट ने परिवहन विभाग को कैबिनेट नोट तैयार करने का निर्देश दिया है।

हजारों छात्रों को भी होगा सुविधा

उन्होंने कहा कि मेट्रो के इस विस्तार से मित्राऊं, सुरहेड़ा गांव, डाबर एक्लेव कॉलोनी, गोपाल नगर कॉलोनी, जाफरपुर गांव के निवासियों के लिए यह विकास एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

एनएसयूटी कैम्पस, आईटीआई जैसे कई शैक्षिक संस्थान रावता मोड़ पर ही हैं तो इससे हजारों छात्रों और शिक्षण संकाय को अपने कॉलेज तक पहुंचने में मदद मिलेगी। राव

तुलाराम अस्पताल में आने वाले बड़ी संख्या में मरीजों को भी सुविधा होगी।

नजफगढ़ से इज़्जर-बादली के लिए अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू

नजफगढ़ में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोट ने शनिवार को नजफगढ़ से हरियाणा के इज़्जर-बादली के लिए अंतरराज्यीय बस सेवा को हरी दिखाकर खाना किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें गद्दा देकर और पानी पीकर सम्मानित किया। इसके बाद कैलाश गहलोट ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि इस अंतरराज्यीय बस के चलने से हरियाणा के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। इज़्जर-बादली के आसपास के कामगार गांव जैसे बादली, खेड़ी जट, खुर्गाई, जहांगीरपुर, बोरिया, बाजितपुर, सिंकेदरपुर, महमूदपुर माजरा, दर्यापुर गांव के लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी। इज़्जर से नजफगढ़ तक यातायात सुविधा शुरू होने से लाखों लोगों को डांबरा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन तक और दिल्ली के लोगों को इज़्जर जिले के गांवों तक आने-जाने में सुविधा होगी।

परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना व प्रौद्योगिकी, गृह एवं महिला व बाल विकास मंत्रालय के मंत्री पदों का कार्य आज से मुख्यमंत्री आतिशी संभालेगी

दिल्ली सरकार में 5 विभागों के मंत्री पदों को सम्भाल रहे कैलाश गहलोट ने मंत्री पदों और आम आदमी पार्टी (आप) की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा

'शीशमहल' और यमुना का किया जिक्र, कहां- 'और कोई विकल्प नहीं बचा था'

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अगले साल दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोट ने रविवार को पार्टी का साथ छोड़ दिया और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। 'आप' के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने इस्तीफे में गहलोट ने पार्टी के सामने मौजूद 'गंभीर चुनौतियों' की ओर इशारा किया। पार्टी के अहम नेता गहलोट ने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए 'शीशमहल' जैसे कुछ 'शर्मनाक' विवादों को भी उठाया और कहा कि इससे सभी को संदेह होता है कि क्या 'हम अब भी खुद को 'आम आदमी' मानते हैं।'

दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में 5 मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोट ने अपने पदों और पार्टी दोनों से आज इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने रजिनेशन लेटर में इसकी वजह भी बताई है।

दिल्ली की राजनीति में आज बड़ी खलबली मच गई है जब कैलाश गहलोट ने अपना आम आदमी पार्टी और मंत्रिपरिषद के पदों से अपना इस्तीफा दिया।

आम आदमी पार्टी की आतिशी सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोट ने मंत्री पद और पार्टी



से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आप से रिजाइन करते हुए राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। कैलाश गहलोट ने पत्र में लिखा है, 'शीशमहल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं, जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं? अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आप से

कैलाश गहलोट
Kailash Gahlot

पूरा पता: डी.डी. नंबर 10002, नए दिल्ली, दिल्ली।
पूरा पता: डी.डी. नंबर 10002, नए दिल्ली, दिल्ली।
पूरा पता: डी.डी. नंबर 10002, नए दिल्ली, दिल्ली।

Dear Hon'ble Minister,

Let me start with sincerely thanking you for having given me the honour of serving and representing the people of Delhi as an MLA and a Minister.

However, at the same time I also want to share with you that today the Aam Aadmi Party faces great challenges. Challenges from within, as the very values that brought us together to AAP, Political ambitions have overtaken our commitment towards people, leading to serious internal divisions. For example the 'Shishmahal', which we had promised to transform into a clean river, but never got around to doing it. How the Yamuna River is getting even more polluted than ever before.

Apart from this, now there are many embarrassing and awkward controversies like the 'SHISHMAHAL' which are now making everyone doubt whether we still believe in being the AAM AADMI.

Another painful point has been the fact that instead of fighting for people's rights we have increasingly only been fighting for our own political agenda. This has severely crippled our ability to even deliver basic services to the people of Delhi. It is now obvious that real progress for Delhi cannot happen if the Delhi Government spends majority of its time fighting with the Centre.

I had started my political journey with the commitment to serve the people of Delhi and I want to continue doing that. Which is why I had never felt with no option but to step away from AAP and hence I resign from primary membership of Aam Aadmi Party.

I wish you the best for your health and future.

I also thank all my party colleagues and well-wishers for their beliefs and kindness throughout this journey.

Sincerely Yours,
KAILASH GAHLOT

कैलाश गहलोट
Kailash Gahlot

पूरा पता: डी.डी. नंबर 10002, नए दिल्ली, दिल्ली।
पूरा पता: डी.डी. नंबर 10002, नए दिल्ली, दिल्ली।
पूरा पता: डी.डी. नंबर 10002, नए दिल्ली, दिल्ली।

Dear Hon'ble Chief Minister,

I hereby tender my resignation from the Council of Ministers, GNCTD.

This may be accepted with immediate effect.

Thanking You,

Sincerely Yours,
KAILASH GAHLOT

लगाते हुए कहा कि जिस ईमानदार राजनीति के चलते पार्टी में वह आए थे, वैसा अब नहीं दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को 'शीशमहल' करार देते हुए उन्होंने कई शर्मनाक और अजीब विवाद हैं, जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने पर विश्वास करते हैं? एक और दुखद बात यह रही है कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय हम केवल अपने स्वयं के राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली का वास्तविक विकास नहीं हो सकता।' उन्होंने पत्र में लिखा 'मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा था' - कैलाश गहलोट

कैलाश गहलोट ने उदाहरण देते हुए लिखा, "यमुना को हमने स्वच्छ नदी में बदलने का वादा किया था, लेकिन कभी ऐसा नहीं कर पाए। अब यमुना नदी शांनद पहले से भी अधिक प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा, अब 'शीशमहल' जैसे कई शर्मनाक और अजीब विवाद हैं, जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने पर विश्वास करते हैं? एक और दुखद बात यह रही है कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय हम केवल अपने स्वयं के राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली का वास्तविक विकास नहीं हो सकता।' उन्होंने पत्र में लिखा 'मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा था' - कैलाश गहलोट

कैलाश गहलोट ने आगे लिखा, "मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं इसे जारी रखना चाहता हूँ, यही कारण है कि मेरे पास आप से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं आपके स्वास्थ्य और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, मैं इस यात्रा के दौरान अपनी पार्टी के सभी सहयोगियों और शुभचिंतकों को उनकी शुभकामनाओं और दयालुता के लिए धन्यवाद देता हूँ।"

आखिर क्यों पड़ते हैं मिर्गी के दौर? जानें इसके लक्षण



विश्व स्तर पर 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है कि मिर्गी को लेकर इसके कारणों और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इस दिन का उद्देश्य कलेक को कम करना और इस स्थिति से पीड़ित व्यक्तियों का समर्थन करना है।

हर साल मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि, यह एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को मिर्गी के कारणों, लक्षणों और उपचार के बारे में शिक्षित करना, मिर्गी को समझने का काम करना है। यह एक ऐसे मंच के रूप में काम करता है जो बीमारी से पीड़ित लोगों का समर्थन करता है, सहयोग और समझ को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, जिसे कई स्वास्थ्य संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है, शोषण निदान और उपचार पर जोर देता है ताकि लोग खुशहाल जीवन जी सकें। यह दिन जागरूकता बढ़ाकर सामाजिक स्वीकृति के महत्व पर जोर देता है और मिर्गी से पीड़ित लोगों की देखभाल और सहायता में सुधार के प्रयासों का समर्थन करता है।

क्यों पड़ते हैं मिर्गी के दौर?
मिर्गी के दौर पड़ने का कई कारण हो सकता है। इससे पिछले समय में सिर की चोट, दिमाग में संक्रमण या ट्यूमर। कई बार तो दिमाग में कोई दिखने वाली समस्या नहीं होती, फिर भी मिर्गी के दौर पड़ने लगते हैं। वहीं, ब्रेन ट्यूमर, संक्रमण, स्ट्रोक, दिमाग में घाव या चोट, ऑटोइम्यून बीमारी जैसी विकार के कारण मिर्गी के दौर पड़ सकते हैं। जब तक व्यक्ति को एक या दो से ज्यादा बार दौरा न पड़े, तब तक मिर्गी के दौरों की पुष्टि तक नहीं होती है।

मिर्गी के लक्षण
वैसे तो मिर्गी असाध्य दामागी एक्टिविटीज के कारण होती है। लेकिन, इससे जुड़े कुछ कॉमन लक्षण दिख सकते हैं।

- बार-बार दौरा पड़ना
- अस्थायी रूप से बेहोश हो जाना
- सोचने की शक्ति मंद हो जाना
- आवाज कम हो जाना
- मांसपेशियों में मरोड़
- सेंसेशन में बदलाव
- बातचीत और समझने में दिक्कत होना
- भय, चिंता या दहशत महसूस करना
- सुन्न महसूस होना
- बोलने या समझने में तकलीफ होना
- अस्थायी रूप से भ्रम होना
- दिल की धड़कन और सांस की गति बढ़ जाना- अपनी सुविधा के अनुसार सांस लेने और छोड़ने की गिनती बराबर रखें।

सर्दियों में इन 5 टिप्स से रखें अपनी त्वचा का रखें ध्यान, नहीं होगी स्किन ड्राई

ठंड के मौसम में त्वचा अधिक बेजान और ड्राई हो जाती है। त्वचा को खिली-खिली और मुलायम बनाने के लिए इन 5 टिप्स का करें प्रयोग, जो त्वचा को सर्दियों में चमकदार बनाएंगी।

ठंड के मौसम में त्वचा का देखभाल करना बेहद जरूरी है। इस मौसम स्किन ड्राई और डल हो जाती है। इस दौरान कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर का सितम जारी है। सर्दियों में सर्द हवाओं से चेहरा बेहद बेजान नजर आता है। चेहरे की सारी रीनक खत्म हो जाती है। विंटर में हमें अपनी स्किन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज हम इस लेख के जरिए विंटर स्किन केयर टिप्स बताते जा रहे हैं।

सर्दी में गर्म पानी से बचें
ठंड के मौसम में गर्म पानी का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। सर्दी में

लोग बहुत ही ज्यादा खोलते गर्म पानी से स्नान करते हैं। जो स्किन के लिए हानिकारक है। सर्दियों में गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही फेस को ठंडे पानी से साफ करें। गर्म पानी स्किन को ड्राई करता है जिससे त्वचा पर खुजली, जलन और सूजन होने लगती है। सर्दी में गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करें।

शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी
सर्दियों में सर्द हवाओं से बचने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना अनिवार्य है। पानी की कमी से स्किन ड्राई हो जाती है। स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।

सनस्क्रीन का प्रयोग जरूर करें
विंटर स्किन रूटीन में सनस्क्रीन इस्तेमाल करना जरूरी है। चाहे धूप हो या बादल सनस्क्रीन चेहरे पर लगाएं। सर्दियों में भी यूवी किरणें स्किन के लिए

खतरनाक होती है। इस मौसम में भी सनस्क्रीन लगाएं इससे त्वचा खिली-खिली नजर आएगी।

होटों पर बादाम तेल लगाएं
इस मौसम सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे होठ होते हैं। सर्द हवाओं से होठ फटने लगते हैं। ऐसे में हमें अपने होठों का विशेष ख्याल रखना है। रात को सोते समय रोजाना होठों पर बादाम का तेल लगाएं। इसके इस्तेमाल से होठ मुलायम हो जाएंगे।

स्किनकेयर रूटीन बदलाव करें
इस मौसम में खान-पान का विशेष ध्यान के साथ-साथ स्किनकेयर रूटीन को फॉलो करना जरूरी है। सर्दियों में स्किन के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो त्वचा को नमी प्रदान करें। इसके लिए आप ग्लिसरीन, माइल्ड क्लींजर, मॉइस्चराइजर आदि का चुनाव कर सकते हैं।



कैंसर का खतरा होगा कम, बस रोजाना करें ये 5 योग

प्रतिदिन योग करने से आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। योग करने से सामान्य स्वास्थ्य बेहतर रहता है। इन 5 योग के करने से कैंसर के खतरे को कम करने में काफी सहायता मिलेगी और स्वस्थ लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।

एक फैक्ट के मुताबिक, कैंसर के लगभग एक-तिहाई मामलों को संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और तनाव मैनेज करके रोका जा सकता है। योग के जरिए और तकनीकों की शक्ति के माध्यम से कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। इन 5 योग के करने से कैंसर के खतरे को कम करने में काफी सहायता मिलेगी और स्वस्थ लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।

कैंसर से बचाव के लिए इन योग टिप्स को

जरूर करें

पर्वतासन कैसे करें

- पहले आराम से बैठो फिर श्वास लें और हथेलियों को एक साथ लाते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर उठाएं।

- सांस छोड़ें और अपनी भुजाएं नीचे करें।

पर्वतासन करने के फायदे

- आपके पेट क्षेत्र के आंतरिक अंगों को आंतरिक आराम मिलता है और ब्लड में काफी सुधार होता है।

- परिसंचरण के सामान्य स्वास्थ्य में सुधार करता है।

- यह मन को शांत रखता है और कैंसर से जुड़े तनाव और चिंता को प्रबंधित करता है।

पवनवृत्तासन कैसे करें

- अपनी पीठ के बल लेटें

- घुटनों को छाती के पास लाएं, उन्हें अपने हाथों से पकड़ें।

- सांस छोड़ते हुए अपने पैर नीचे करें।

इसके फायदे

- यह पेट के एरिया को हल्का दबाव प्रदान करता

है, जिससे गैस और सूजन से राहत मिलती है।

- यह पाचन को दुरुस्त रखता है जो कैंसर को रोकने के लिए आवश्यक है।

शवासन कैसे करें

- अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपनी बाहों को अपने शरीर से लगभग एक फुट की दूरी पर फैलाएं, पैरों को थोड़ा अलग रखें।

- हथेलियां ऊपर की ओर रखें और आंखें बंद करके शव की तरह आराम करें।

- बिना हिले-डुले, क्रम से शरीर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें, पैर की उंगलियों से शुरू करके सिर के शीर्ष तक।

शवासन करने के फायदे

- इससे तनाव को कम किया जाता है जो सूजन और कैंसर के खतरे में योगदान देता है।

- नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ और शरीर की मरम्मत के लिए जरूरी है।

प्राणायाम कैसे करें

- पीठ के बल लेट जाएं और घुटनों को कूल्हों के



पास ऊपर खींचें।

- एक हाथ अपने पेट पर और दूसरा हाथ शरीर के बागल में रखें।

- अपनी आंखें बंद करें और पेट को ऊपर की ओर लाते हुए धीरे से सांस लें।

- जैसे ही सांस लेना पूरा हो जाए, आराम से सांस छोड़ें, पेट के गिरने या अंदर धंसने के प्रति सचेत रहें।

जानें इसके फायदे

- अपनी सुविधा के अनुसार सांस लेने और छोड़ने की गिनती बराबर रखें।

- विश्राम को बढ़ावा देता है, तनाव और कैंसर जैसे इससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करता है।

- फेफड़ों की क्षमता में सुधार, श्वसन स्वास्थ्य में सहायता।

आइस क्यूब ट्रे को इन अमेजिंग तरीकों से भी किया जा सकता है इस्तेमाल

आइस क्यूब ट्रे की मदद से आप कई छोटी-बड़ी आइटम्स को आसानी से आर्गेनाइज कर सकती हैं। मसलन, आइस क्यूब ट्रे आपके लिए ज्वैलरी आर्गेनाइजर की तरह काम कर सकता है। इसकी मदद से आप इयररिंग, रिंग या छोटे ब्रेसलेट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

आइस क्यूब ट्रे का इस्तेमाल अमूमन घरों में किया ही जाता है। हम सभी इसका इस्तेमाल बर्फ जमाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी आइस क्यूब ट्रे को एक अलग तरह से इस्तेमाल करने के बारे में सोचा है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन आइस क्यूब ट्रे को कई अलग-अलग बेहतरीन तरीकों से भी काम

में लाया जा सकता है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि आप आइस क्यूब ट्रे को किन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है-

आर्गेनाइजिंग में करे मदद

आइस क्यूब ट्रे की मदद से आप कई छोटी-बड़ी आइटम्स को आसानी से आर्गेनाइज कर सकती हैं। मसलन, आइस क्यूब ट्रे आपके लिए ज्वैलरी आर्गेनाइजर की तरह काम कर सकता है। इसकी मदद से आप इयररिंग, रिंग या छोटे ब्रेसलेट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, इसमें मोतियों, बटन या पिन्स को अलग-अलग सेक्शन में रखा जा सकता है। इसकी मदद से आपको छोटी-छोटी आइटम्स को स्टोर करने में काफी आसानी होती है।

ब्यूटी और स्किनकेयर प्रोडक्ट को करें स्टोर

आइस क्यूब ट्रे आपकी स्किन की केयर करने में भी मददगार है। अगर आप सनबर्न या

स्किन इरिटेशन में आराम पाना चाहते हैं तो ऐसे में आप एलोवेरा जेल को फ्रीज करें। वहीं, आंखों की सूजन को कम करने बची हुई कॉफ़ी से आइसक्यूब बनाकर इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपके लिए अपनी स्किन की देखभाल करना काफी आसान हो जाता है और इससे आपके काफी सारे पैसों भी आसानी से बचते हैं।

गार्डनिंग में आया काम

अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो ऐसे में आप आइस क्यूब ट्रे की मदद ले सकते हैं। आइस क्यूब ट्रे को बतौर बीज स्टार्टर ट्रे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आप आइस क्यूब ट्रे के अंदर कंपार्टमेंट्स को मिट्टी से भरें और घर के अंदर अंकुरित होने के लिए बीज लगाएं। एक बार जब पौधे अंकुरित हो जाएं, तो उन्हें गमलों या बगीचे में रोप दें। इस तरीके को अपनाया इसलिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे बीजों को अंकुरित होने के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्राप्त होता है।



प्रस्तावित परिसीमन से भारत के संघीय ढांचे को खतरा

परिसीमन उच्च-विकास वाले राज्यों की ओर शक्ति को झुका सकता है, जिससे उच्च कुल प्रजनन दर वाले उत्तरी राज्यों को संघीय मामलों में अधिक नियंत्रण मिल सकता है। बिहार और यूपी को अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं, जिससे सभी राज्यों को प्रभावित करने वाली केंद्रीय नीतियों पर उनका प्रभाव बढ़ सकता है।

-प्रियंका सौरभ

भारत में परिसीमन अभ्यास, जिसकी देखरेख राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श से नियुक्त परिसीमन आयोग द्वारा की जाती है, का उद्देश्य जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों को फिर से संगठित करना है, जिससे प्रतिनिधि शासन सुनिश्चित हो सके। हालांकि, यह प्रक्रिया कुछ लोगों के लिए संभावित नुकसान के बारे में चिंताएँ पैदा करती है, जिससे राष्ट्र के संघीय ढांचे पर असर पड़ता है। नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि वाले दक्षिणी राज्यों में कम प्रतिनिधित्व के कारण संघ के निर्णयों में प्रभाव कम होने का जोखिम है। तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, जिससे उच्च सकल घरेलू उत्पाद योगदान के बावजूद राष्ट्रीय मुद्दों में इसकी आवाज प्रभावित हो सकती है। परिसीमन उच्च-विकास वाले राज्यों की ओर शक्ति को झुका सकता है, जिससे उच्च कुल प्रजनन दर वाले उत्तरी राज्यों को संघीय मामलों में अधिक नियंत्रण मिल सकता है। बिहार और यूपी को अतिरिक्त सीटें मिल सकती हैं, जिससे सभी राज्यों को प्रभावित करने वाली केंद्रीय नीतियों पर उनका प्रभाव बढ़ सकता है।

उच्च जनसंख्या वाले राज्यों के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाने से उन क्षेत्रों के पक्ष में संसाधनों का पुनर्वितरण हो सकता है, जिससे समान विकास प्रभावित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के लिए अतिरिक्त सीटें अधिक केंद्रीय निधि प्राप्त कर सकती हैं, जबकि केरल जैसे कम प्रतिनिधित्व

वाले राज्यों को कम संसाधन मिल सकते हैं। अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व और संसाधनों तक पहुँच असमान विकास को जन्म दे सकती है, जिससे कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र अलग-थलग पड़ सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों ने ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व के कारण विकास में हाशिए पर रहने का अनुभव किया है, एक ऐसी स्थिति जो नए परिसीमन के साथ और भी खराब हो सकती है। कम सीटों और संसाधनों के कारण हाशिए पर महसूस करने वाले छोटे राज्य अलगवादी भावनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है। सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के अलग-थलग महसूस करने का जोखिम बढ़ सकता है यदि उन्हें लगता है कि उनकी चिंताओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिससे संघ की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो सकता है।

हिंदी भाषी राज्यों में अधिक प्रतिनिधित्व गैर-हिंदी क्षेत्रों को हाशिए पर डाल सकता है, जिससे सांस्कृतिक समानता के बारे में चिंताएँ बढ़ सकती हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रभाव में कमी आ सकती है, जिससे सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा की माँग बढ़ सकती है। अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व चुनिंदा क्षेत्रों में सत्ता को केंद्रीकृत कर सकता है, जिससे राज्य की स्वायत्तता कम हो सकती है और सहकारी संघर्षवाद कमजोर हो सकता है। दक्षिणी राज्य केंद्रीय नीतियों को उत्तरी हिंदों से अत्यधिक प्रभावित मान सकते हैं। कम जनसंख्या वृद्धि लेकिन उच्च कर योगदान वाले राज्यों में कम प्रतिनिधित्व हो सकता है, जिससे राजकोषीय असमानताओं का खतरा हो सकता है। यदि सीट आवंटन कम उत्पादक क्षेत्रों के पक्ष में होता है, तो महाराष्ट्र को कम केंद्रीय निधि का सामना करना पड़ सकता है। उच्च-कुल प्रजनन दर वाले राज्यों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व असमान संसाधन आवंटन की ओर ले जा सकता है, जिससे विकसित राज्यों की केंद्रीय निधियों तक पहुँच प्रभावित हो सकती है।



उत्तर प्रदेश को अधिक केंद्रीय निधियाँ मिल सकती हैं, जबकि कर्नाटक जैसे योगदान देने वाले राज्यों को बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से उन्नत राज्यों के लिए कम प्रतिनिधित्व राजस्व-केंद्रित नीतियों को प्राथमिकता से हटा सकता है, जिससे राजकोषीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है। औद्योगिक नीति पर तमिलनाडु का इनपुट कम हो सकता है, जिससे राष्ट्रीय राजस्व पहल प्रभावित हो सकती है। उच्च कुल प्रजनन दर (राज्यों) के पक्ष में पुनर्वितरण से उन राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना आवंटन में वृद्धि हो सकती है, संभवतः कम कुल प्रजनन दर वाले राज्यों की कीमत पर। बिहार जैसे उच्च-जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक योजना निधि मिल सकती है, जबकि तमिलनाडु जैसे नियंत्रित

जनसंख्या और महत्वपूर्ण योगदान वाले राज्यों को कार्यक्रम निधि में कमी देखने को मिल सकती है। राज्यों को जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहन खोना पड़ सकता है। केरल जैसे प्रभावित परिवार नियोजन राज्यों को कम राजकोषीय लाभ मिल सकता है, संभवतः अन्य राज्यों को समान प्रयासों से हतोत्साहित कर सकता है।

असंतुलन क्षेत्रों के बीच अधिक आय असमानता की ओर ले जा सकता है, संभवतः असमानता के रूप से विवश क्षेत्रों से अधिक विकसित राज्यों में प्रवास प्रवाह को बढ़ावा दे सकता है। प्रति राज्य लोकसभा सीटों की सीमा तय करने से क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए

संभावित समाधान सामने आएंगे। प्रति राज्य सीटों को सीमित करने से संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है और अधिक आबादी वाले राज्यों द्वारा असंगत प्रभाव को रोका जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने सीटों की सीमा 435 (1913 से) तय की है, जो कुल संख्या का विस्तार किए बिना राज्यों के बीच पुनर्वितरण करती है, जिससे संतुलित राज्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। सीटों को अनुपातिक रूप से जोड़ने से जनसंख्या-नियंत्रित राज्यों को दंडित किए बिना लोकतांत्रिक विस्तार की अनुमति मिलती है। जर्मन बुडेस्टैग मिश्रित-सदस्यीय दृष्टिकोण का उपयोग करता है, विशेष क्षेत्रों को नुकसान पहुँचाए बिना अनुपातिकता बनाए रखने के

लिए आवश्यकतानुसार सीटें जोड़ता है। राज्यसभा की भूमिका बढ़ाने से क्षेत्रीय हितों में वृद्धि होती है, क्योंकि यह आबादी के बजाय राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है।

राज्यसभा का प्रभाव बढ़ाने से यूरोपीय संघ की घटती आनुपातिकता को प्रतिबिंबित किया जा सकता है, जहाँ कम आबादी के बावजूद छोटे सदस्य राज्य महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व बनाए रखते हैं। अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने से जनसंख्या-नियंत्रण प्रयासों को पुरस्कृत किया जाता है, जिससे केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजकोषीय निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। कम प्रतिनिधित्व के बावजूद केरल और तमिलनाडु को लक्षित विकास निधि मिल सकती है। परिसीमन पर एक और रोक लगाने से प्रतिनिधित्व में अचानक बदलाव के बिना स्थिरता और नीति अनुकूलन की अनुमति मिलती है। फ्रीज को बढ़ाने से जनसंख्या में होने वाले बदलावों के साथ क्रमिक समायोजन की अनुमति मिलेगी, जिससे संघीय सद्भाव बना रहेगा। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सम्बोधित करने में संघीय ढांचे के भीतर क्षेत्रीय भाषाओं, परंपराओं और प्रथाओं का सम्मान करने वाली नीतियों को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक विशिष्टता को मान्यता देना शामिल है। विशेष विधायी उपाय या विकास अनुदान मजबूत क्षेत्रीय पहचान वाले राज्यों में सांस्कृतिक संरक्षण का समर्थन कर सकते हैं, यूरोपीय संघ में सदस्य-राज्य विविधता को बढ़ावा देने वाली सांस्कृतिक नीतियों के समान।

अंतर-राज्य परिपक्व जैसे सशक्त मंच क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देते हैं, क्षेत्रीय तनाव को कम करते हैं और सहकारी संघर्षवाद के माध्यम से शिकायतों का समाधान करते हैं। परिसीमन की कवायद भारत के संघीय ढांचे और राजकोषीय इक्विटी के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ लाती है, जिससे प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने वाले समाधानों की आवश्यकता होती है।

आम आदमी पार्टी की चोट पर लगा मरहम! गहलोत के जाने के बाद इस भाजपा विधायक ने ज्वाइन की पार्टी



परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2024 से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और किराड़ी से विधायक अनिल झा ने पार्टी छोड़कर आप का दामन थाम लिया है। अनिल झा को आप किराड़ी से टिकट दे सकती है। इस सीट से वर्तमान में आप के त्रिलोकपुरी विधायक हैं। अनिल झा 2008 से 2013 तक इस सीट से भाजपा से विधायक रहे हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (AAP Arvind Kejriwal) ने भाजपा से किराड़ी से विधायक रहे अनिल झा को आप ज्वाइन कराई। झा को मिल सकती है किराड़ी से टिकट। इस समय आप के इस सीट से विधायक त्रुराज झा हैं।

अनिल झा 2008 से 2013 इस सीट से भाजपा से विधायक रहे हैं। झा 32 सालों तक भाजपा में रहे हैं इस सीट पर पूर्वांचल के बड़े नेता माने जाते हैं।

केजरीवाल ने अनिल झा को लेकर क्या कहा?

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने 10,000 किलोमीटर सड़कें और गलियां बनाईं,

6800 किलोमीटर सीवर लाइनें बिछाईं और 1,650 अनधिकृत कालोनियों में पाइप से पानी उपलब्ध कराया, लेकिन रूभाजा ने कुछ नहीं किया कहा कि मैं भाजपा और उसके नेता अमित शाह से पूछना चाहता हूँ कि पूर्वांचली लोगों को पार्टी को बोट क्यों देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि वे दिल्ली में पूर्वांचली लोगों के लिए एक काम बताएं। उन्होंने इन कालोनियों में संपत्तियों को रजिस्ट्री का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया। एक भी काम पांच साल में किया जा सकता है। हालांकि, पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर केजरीवाल ने आप से गहलोत के इस्तीफा पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

गहलोत के जाने पर क्या बोले पूर्व सीएम

अब लोगों के रिश्ते भी आ रहे हैं और लोग सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। कैलाश गहलोत के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में दो सरकारें हैं, केन्द्र के पास बहुत पैसा है। मगर दिल्ली सरकार एक भी काम बता दे कि जो उन्होंने दिल्ली में किया है। उन्होंने दिल्ली में क्या काम किया है। ये लोग केवल गंदी राजनीति ही कहते हैं।

भाजपा का ईडी-सीबीआई के दम पर चुनाव दुर्गेश पाठक ने गहलोत पर सवाल के जवाब में

कहा कि भाजपा दिल्ली में ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) को दम पर चुनाव लड़ना चाहती है, हम दिल्ली की जनता के दम पर चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना से साफ हो गया है कि भाजपा दिल्ली में चुनाव हार चुकी है।

गहलोत का पार्टी से इस्तीफा वहीं, सुबह के समय आप को झटका देते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गहलोत ने इस संबंध में सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर जानकारी दी है।

कैलाश गहलोत ने आप से इस्तीफा देते हुए केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा है, रसबसे पहले मैं आपको एक विधायक और एक मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व करने का सम्मान देने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि आज आम आदमी पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां पार्टी के भीतर से हैं, उन्हीं मूल्यों से जुड़ी हैं जिनके कारण हम आम आदमी पार्टी में आए हैं।

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी करेंगे उद्घाटन

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित *43वें विश्व व्यापार मेले* में एक बार फिर परंपरा, क्राफ्ट, कला एवं संस्कृति से सरबो सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन किया गया है। *केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर)* द्वारा समर्थित सरस आजीविका मेला 2024 का उद्घाटन सोमवार को *केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी* करेंगे। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के *सचिव शैलेश कुमार सिंह* भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन के साथ ही राज्य मंत्री डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी विभिन्न राज्यों से आई हुई सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के स्टॉलों पर जाकर उनका प्रोत्साहन भी करेंगे। साथ ही उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों का अवलोकन भी करेंगे।

वहीं, आज संडे के दिन सरस मेला में काफी भीड़ रही। इस दौरान लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। इस दौरान ग्रामीण कलाओं का लोगों ने काफी सराहना भी किया। साथ ही विभिन्न खाद्य पदार्थों के स्टॉलों पर भी अच्छी खासी खरीदारी हुई।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा



आयोजित *सरस आजीविका मेला 2024* में ग्रामीण भारत की शिल्पकलाओं का मुख्य रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलने वाले इस उत्सव में 31 राज्यों की 300 से अधिक महिला शिल्प कलाकार, 150 से अधिक स्टॉलों *पर अपनी-अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शनी का प्रदर्शन व बिक्री कर रही हैं। ज्ञात हो कि सरस आजीविका मेला भारत मंडपम के *हॉल नंबर - 9 और 10* में लगाया गया है। सरस आजीविका मेला के दौरान देश भर के 10* में लगाया गया है। सरस आजीविका मेला के दौरान देश भर के 10* में लगाया गया है। सरस आजीविका मेला के दौरान देश भर के 10* में लगाया गया है।

मिल सके। ताकि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत का संकल्प व "वोकल फॉर लोकल" अभियान को बढ़ावा मिल सके। साथ ही प्रधानमंत्रीजी के ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का सपना भी साकार हो सके। सरस को इस बार लखपति दीदियों पर फोकस किया गया है। यही कारण है कि सरस को पांच जेन में लखपति दीदियों के राज्यों के हिसाब से बांटा गया है। इसके अन्तर्गत लखपति दीदी जोन एक में जहां नार्थ-ईस्ट के राज्य हैं वहीं, जोन दो में साउथ इंडियन स्टेट्स हैं। इसके साथ ही जोन तीन में जहां उत्तर भारतीय राज्य हैं वहीं, जोन चार में उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य हैं। साथ ही जोन पांच में बिहार झारखंड समेत पूर्वांचल समेत अन्य राज्य हैं।

जमाअत का अखिल भारतीय सदस्य सम्मेलन एक बेहतर विश्व के निर्माण की नए जोश के साथ संपन्न हुआ

सुषमा रानी

नई दिल्ली। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद का अखिल भारतीय सदस्य सम्मेलन रविवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। सम्मलेन में रन्याय और समानता की स्थापना के विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अमीर (अध्यक्ष) सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने जमाअत के केडर से सत्य और न्याय के सिद्धांतों पर समाज के पुनर्निर्माण के मिशन के प्रति खुद को फिर से समर्पित करने का आह्वान किया।

सम्मेलन में समापन भाषण में जमाअत के अमीर ने सदस्यों को संगठन के सदस्य बनते समय संगठन की सेवा करने की पवित्र प्रतिज्ञा की याद दिलाई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची प्रतिबद्धता के लिए सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति न केवल आस्था को अपनाता है, बल्कि सक्रिय रूप से इसे अपने आस-पास के वातावरण में भी प्रसारित करता है।

सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने सदस्यों से आपसी समर्थन, सहयोग और एकता प्रदर्शित करने का आह्वान किया और बताया कि एक मजबूत सामूहिक मोर्चे को बनाए रखने के लिए ये अपरिहार्य हैं। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के सदस्यों को छोटे-मोटे मुद्दों में न उलझने की सलाह दी गई, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व के बड़े उद्देश्य से ध्यान भटका सकते हैं। इसे सुदृढ़ करने के लिए उन्हीं व्यक्तिगत चिंतन के महत्व पर बल



दिया तथा सदस्यों को याद दिलाया कि सच्चा समर्पण व्यक्ति के धार्मिक दायित्वों को निभाने, पारिवारिक बंधनों को पोषित करने तथा जीवन के सभी पहलुओं में सच्चाई और विश्वास को अपनाने से शुरू होता है। जमाअत के अमीर जमाअत ने मूल्य आधारित समाज के निर्माण के मिशन की स्थायी सफलता के लिए आत्म-जवाबदेही, निरंतर आध्यात्मिक कायाकल्प और नैतिक मूल्यों को कायम रखने पर जोर दिया।

सम्मेलन के अंतिम दिन देश के विभिन्न

भागों से विशेष स्थानीय और राज्य स्तर के नेता अपने सर्वोत्तम संगठनात्मक अनुभवों को प्रतिभागियों के साथ साझा किया तथा उन्हें संगठनात्मक विकास और सामाजिक पैठ के लिए नए विचार और रणनीतियां प्रदान कीं।

सम्मेलन में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसमें आध्यात्मिकता, अंतर-धार्मिक संवाद, मानवविकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। एक विशेष प्रदर्शनी, 'इद्राक तहरीक शोकेस'

(IDRAK Tahreek Showcase) में देश भर में चल रहे 100 से अधिक सफल सामुदायिक और सामाजिक विकास कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया गया।

सम्मेलन के मुख्य आयोजक अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने सभी प्रतिभागियों, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, अन्य संबंधित अधिकारियों और लगभग 1500 से अधिक स्वयंसेवकों को मजबूत टीम को इस विशाल आयोजन को सुविधाजनक बनाने में उनके समर्पित प्रयासों, समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

वक्फ लिबरेशन मूवमेंट द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

आजमी मेडिकल सेंटर ओखला का एक मात्र चिकित्सा केंद्र है जहां जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज किया जाता है: शाहिद अली एडवोकेट

नई दिल्ली। वक्फ लिबरेशन मूवमेंट द्वारा आजमी मेडिकल सेंटर, ठाकर नं. 5/अबुल फजल, ओखला में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सभी रोगों के साथ साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक उपस्थित थे। शिविर में सभी मरीजों को निःशुल्क जांच के साथ-साथ निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गईं। शिविर में लगभग 130 मरीज लाभान्वित हुए।

इस अवसर पर वक्फ लिबरेशन मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहिद अली एडवोकेट ने कहा कि हमारा उद्देश्य सामाजिक सेवाओं के माध्यम से समाज की बेहतर में योगदान करना है। हम लगातार सामाजिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। हमारा लक्ष्य लोगों के जीवन में खुशी लाना है। हम हमेशा इस लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करना है क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाले बड़ी संख्या में लोगों का जीवन कठिन है, जिसके कारण उन्हें अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है, इसलिए इस शिविर की स्थापना की गई ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आजमी मेडिकल सेंटर के काम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ओखला में आजमी मेडिकल सेंटर ही एकमात्र केंद्र है जहां जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है।

आजमी मेडिकल सेंटर के निदेशक डॉ. ज़मीर आजमी ने कहा कि आज के शिविर में बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए। उन्होंने बताया कि आजमी मेडिकल सेंटर में हर दिन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक गरीबों का इलाज निःशुल्क किया जाता है और हर शुरुवार को शुगर की जांच भी निःशुल्क की जाती है इसके अलावा, टेस्ट में 50% की छूट दी जा रही है।



गहलोत का इस्तीफा: ईडी-सीबीआई की जांच, एलजी से नजदीकियां... विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तरह न हो जाए आप का हश्रा

रितेश राव

दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैलाश गहलोत के इस्तीफे ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। गहलोत के पास परिवहन प्रशासनिक सुधार सूचना व तकनीक गृह महिला व बाल विकास विभाग थे। उनके इस्तीफे से पार्टी को लोकसभा चुनाव की तरह ही इस चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ सकता है।

नई दिल्ली। गत लोकसभा चुनाव की तरह ही दिल्ली विधानसभा चुनाव से भी ठीक कैलाश गहलोत के मंत्री पद से इस्तीफा देने से आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक जानकार इसे लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी देख रहे हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव की तरह ही इस चुनाव के प्रभावित हो जाने की आशंका भी है।

इस्तीफा देने वाले गहलोत (Kailash Gehlot Resign) दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल स्तंभ

माने जा रहे थे। उनके पास परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना व तकनीक, गृह, महिला व बाल विकास विभाग थे। उनके दो विभागों में सरकार के अन्य विभागों में अधिक काम देखा जा रहा था।

एलजी सक्सेना से थे अच्छे संबंध

एलजी वीके सक्सेना (LG VK Saxena) के साथ अच्छे संबंध होने के चलते सरकार में काम कराने का भी गहलोत को लाभ मिल रहा था।

गहलोत के प्रमुख विभागों में महिला व बाल विकास विभाग और परिवहन विभाग मुख्य रूप से शामिल हैं।

इलेक्ट्रिक बसों की सफलता दिल्ली में आ रही इलेक्ट्रिक बसों की सफलता गहलोत का एलजी के साथ बेहतर तालमेल के कारण ही संभव माना जा रहा था। महिलाओं को



एक-एक हजरत रुपये देने वाली जो महिला सम्मान योजना जमीन उतारने की सरकार कोशिश कर रही थी, वह योजना भी उनके महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित थी।

गहलोत ने केजरीवाल को बताया था आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी

गहलोत का दिल्ली सरकार में गत 15 अस्त को उस समय कद बढ़ गया था जब एलजी वीके सक्सेना ने उन्हें सरकार का श्रेष्ठ मंत्री बताया था और केजरीवाल सरकार के झंडा फहराने के आतिशी को किए गए प्रस्ताव को दरकिनार कर गहलोत को दे दिया गया था।

दिल्ली में अपने संगीत जगत के स्वर्णिम 50 साल का जश्न मनाएंगे पद्मश्री हरिहरन

परिवहन विशेष न्यूज

इस खास मौके अपना आभार व्यक्त करते हुए हरिहरन ने कहा यह संगीत जगत में मेरी अविश्वसनीय यात्रा के लिए आभार है कि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उन सभी के संगीत का उत्सव है जिन्होंने भारतीय संगीत की समृद्धि में योगदान दिया है। 30 नवम्बर की शाम का मुझे बेसब्री से इंतजार है

पूर्वी दिल्ली। भारत - संगीत के दिग्गज और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित हरिहरन जी ने आधिकारिक तौर पर

भारतीय संगीत उद्योग में अपने उल्लेखनीय 50 वर्षों के योगदान का जश्न मनाने के लिए दिल्ली में एक ऐतिहासिक लाइव कॉन्सर्ट का ऐलान किया। आगामी 30 नवंबर को हरिहरन जी के सभी चाहने वालों के लिए यादगार शाम का वादा किया है, जिसमें भारत के अनेक प्रसिद्ध गायकों और बॉलीवुड के दिग्गज इस कॉन्सर्ट में चार चाँद लगा देंगे, साथ ही इस खास अवसर पर हरिहरन जी ने ऐलान किया कि उनके चाहने वाले जो उनसे मिलना चाहता है वह उनके ही गाने पर अपनी वीडियो बना कर हेल्प आर्टिस्ट इंडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कॉल ब्रेट करेगा

उनमें से 50 लोगों को उनके द्वारा सिग्नेचर वाला गिटार से सम्मानित किया जायेगा। हरिहरन जी ने आगामी लाइव कॉन्सर्ट के बारे में अपना उत्साह साझा किया, और वादा किया कि प्रशंसकों के लिए एक सफर है। पांच दशक के लंबे करियर में अपने सबसे बड़े हिट गाने प्रस्तुत करने के अलावा, संगीत कार्यक्रम में कई शीर्ष भारतीय गायक भी शामिल होंगे जिनकी पहचान को फैंस के सरप्राइज के लिए गुप्त रखा जा रहा है। भारतीय संगीत जगत की कई जानी मानी हस्तियां एवं बॉलीवुड के कलाकारों को एकजुट करते हुए, यह कॉन्सर्ट दिल्ली

वालों के लिए यादगार साबित होगा। इस खास मौके अपना आभार व्यक्त करते हुए, हरिहरन ने कहा, 'यह संगीत जगत में मेरी अविश्वसनीय यात्रा के लिए आभार है, कि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। यह सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि उन सभी के संगीत का उत्सव है, जिन्होंने भारतीय संगीत की समृद्धि में योगदान दिया है। मैं 30 नवम्बर की शाम का मुझे बेसब्री से इंतजार है क्योंकि दिल्ली वाले सच में दिल में बसते और बसाते हैं, और यह मेरा सौभाग्य होगा कि इस शाम को सभी चाहने वालों के लिए यादगार हो।

इस कॉन्सर्ट में देश और विदेश के कई जाने माने ब्रॉड शामिल होंगे, यहां आने वाले लोगों के लिए आकर्षित व्यंजनों से लेकर अनेकों प्रकार के स्टाल्स का लुप्त उठाने का मौका मिलेगा। यह कॉन्सर्ट उन सभी संगीत प्रेमी के लिए अनूठा जश्न का माहौल प्रदान करेगा और यह दिल्लीवासियों की तरफ से हरिहरन जी के 50 वर्षों के इस सफर को जश्न में बदल कर देगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को व्यापक अपील पर प्रकाश डाला। भारतीय बॉलर शेख अब्दुल हमीद ने

महान गायक के प्रति अपनी प्रशंसा साझा की और कहा, "बॉलिंग की तरह, संगीत भी भारत की आत्मा में गहराई से समाया हुआ है। हरिहरन की आवाज वर्षों से मेरे जैसे प्रशंसकों के लिए एक निरंतर साथी रही है, और इस उत्सव का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है।" हेल्प आर्टिस्ट इंडिया के संस्थापक अशोक राजपूत ने भी संगीत कार्यक्रम के सांस्कृतिक महत्व के बारे में बात की और कहा, "हरिहरन जी जैसे कलाकार कई पीढ़ियों को प्रेरित करते आये हैं और उनकी 50 साल के दृढ़ता, जुनून और संगीत के प्रति प्रेम भरी इस यात्रा को हम

सबका प्रणाम है। मुझे और हेल्प आर्टिस्ट इंडिया को इस आयोजन का समर्थन करने पर गर्व है, जो रचनात्मक प्रतिभाओं को उभारने और जश्न मनाने के महत्व को दर्शाता है। क्योंकि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के सिलेक्ट उद्घोष होने की उम्मीद है। यह कॉन्सर्ट सिर्फ एक प्रदर्शन से कहीं अधिक है - यह 50 साल की विरासत का जश्न है जिसने भारतीय संगीत उद्योग को आकार दिया है, जो दुनिया के कुछ सबसे सम्मानित ब्रॉडों द्वारा संचालित है और इसमें एक आश्चर्यजनक संयोग है जिसे प्रशंसक मिस नहीं करना चाहेंगे।

फरीदाबाद से अब नोएडा और गाजियाबाद आना-जाना होगा आसान, ये शानदार प्रोजेक्ट बनकर तैयार

परिवहन विशेष न्यूज

फरीदाबाद से नोएडा और गाजियाबाद आना और जाना अब आसान होने वाला है। राहगीरों को या वाहन चालकों को भारी ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने की दिशा में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। इसके अलावा पूर्व से पश्चिम फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को लेकर भी प्रशासन गंभीर दिखाई दे रहा है। इन दोनों परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है।

फरीदाबाद। फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद और पूर्व से पश्चिम फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को लेकर प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। दोनों परियोजनाओं को सिरे चढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। इन दोनों परियोजनाओं पर करीब 2431 करोड़ रुपये की लागत आएगी। फरीदाबाद व गुरुग्राम से अधिकतर लोगों को आवागमन नोएडा की ओर रहता है। फिलहाल यह स्थिति है कि गुरुग्राम से नोएडा के लिए करीब दो

घंटे से अधिक तथा फरीदाबाद से नोएडा की दूरी करीब 40 किलोमीटर की है। ऐसे में आमजन को रोजाना सड़कों पर जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने एफएमडीए और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों संग दोनों परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद रूट प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू करने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है।

जिसके बनने से फरीदाबाद से नोएडा की दूरी महज 10 किलोमीटर की रह जाएगी और लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। करीब 900 करोड़ की राशि से फरीदाबाद-नोएडा के इस एफएनजी मार्ग की कनेक्टिविटी फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल के पास से शुरू होकर नोएडा के सेक्टर-168 तक रहेगी। वहीं पूर्व से पश्चिम शहर की सीधी कनेक्टिविटी होने से बनने से गुरुग्राम तक के लोगों को एफएनजी से सीधा लाभ पहुंचेगा।

पूर्व-पश्चिमी शहर की कनेक्टिविटी

शहरी क्षेत्र को जाम मुक्त बनाने वाली पूर्वी शहर की पश्चिमी शहर से कनेक्टिविटी की दिशा में भी काम हो रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य नहर पर ग्रेटर फरीदाबाद के एरिया को एनआईटी के आखिरी छोर से जाममुक्त कनेक्ट करना है। इसके तहत दो रूट प्रस्तावित हैं जिसमें एक बाटा चौक तथा बडखल का रूट शामिल है।

बाटा रूट

बाटा रूट पर चार फ्लाईओवर जो मस्जिद चौक, प्याली चौक, हाईवेपर चौक तथा 15-15ए डीसी रोजिडेंस रोड से इंडियन आयल चौक फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है। वहीं इस रूट पर मस्जिद चौक मुल्ला होटल पर एक कनेक्टिंग फ्लाईओवर तथा गुडईयर चौक, बाटा चौक (दिल्ली साइड) एवं बीपीटीपी चौक बाईपास रोड पर तीन यू-टर्न और नेशनल हाईवे पर एक अंडरपास का निर्माण प्रस्तावित है।

इस रूट के निर्माण के बाद नहर पर से गुरुग्राम मोड़ तक पहुंचने का समय केवल 10 मिनट ही रहेगा जिस पर अभी 40 से 45 मिनट



लगाते हैं। यह नौ किलोमीटर लंबा रूट छह लेन का होगा जिसके निर्माण पर करीब 683 करोड़ रूपए का खर्च होगा।

बडखल रूट

बडखल रूट पर भी कार्य को शुरूआत होगी जिसमें पांच फ्लाईओवर, पांच एलिवेटेड यू-टर्न और एक कनेक्टिंग फ्लाईओवर का निर्माण

प्रस्तावित है। इस रूट पर गुरुग्राम मोड़, सैनिक कालोनी टी पाईट, बडखल गंज, अनखीर चौक तथा 28-29 तिरंगा रोड पर फ्लाईओवर तथा गुरुग्राम मोड़।

सैनिक कालोनी टी पाईट, नेशनल हाईवे पर दिल्ली एवं मथुरा साइड और बाईपास रोड सेक्टर-29 रेडलाइट दिल्ली पल्ला की ओर

एलिवेटेड यू-टर्न का निर्माण किया जाएगा।

इसी के साथ अनखीर चौक पर एक कनेक्टिंग फ्लाईओवर का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस आठ किलोमीटर लंबे रूट पर करीब 849 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके साथ, अग्रोच रोड, सर्विस रोड और ड्रेनेज सुविधाओं को पूरा किया जाना है।

सात फरवरी से शुरू होगा सूरजकुंड मेला, इस बार कई वजहों से होगा खास



परिवहन विशेष न्यूज

38th Surajkund Crafts Mela अगले साल के फरवरी महीने में शुरू होने वाले 8वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की तैयारी शुरू हो गई है। इस साल का मेला कई कारणों से खास होने वाला है। इस बार के हस्तशिल्प मेले में बिम्स्टेक की प्रमुख भागीदारी होगी। मेले में 1100 हटस बनेंगी। पर्यटकों को मेले में आने के लिए छह वीकेंड मिलेंगे।

फरीदाबाद। हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से लगने वाले 38वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की तैयारी शुरू कर दी गई है। नए वर्ष में सात फरवरी, शुक्रवार से शुरू होकर यह मेला 23 फरवरी रविवार तक चलेगा।

ऐसे में पर्यटकों को छह वीकेंड यानी तीन शनिवार और तीन ही रविवार को मेले का दीदार

करने का मौका मिलेगा। इस बार मेले में बिम्स्टेक की प्रमुख भागीदारी रहेगी। बिम्स्टेक सात देशों का एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड सदस्य हैं।

इस बार मेले में 1100 से अधिक हटस थीम स्टेट का अभी चयन नहीं हो पाया है। मेले में देश-विदेश के शिल्पी भाग लेंगे। मेले से बिम्स्टेक के जुड़ने के साथ ही सूरजकुंड परिसर में तैयारी शुरू की गई है। इस बार मेले में 1100 से अधिक हटस होंगी। वीआईपी गेट के पास पहले से ही कई हटस तैयार हैं। आमतौर पर यहीं थीम स्टेट जोन बनाया जाता है।

इस बार दिल्ली गेट के पास बड़ी चौपाल पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। एक चौपाल वीआईपी गेट के पास है और दूसरी चौपाल छत्तीसगढ़ गेट के नजदीक निचले हिस्से में है। ऐसे में मेले में तीन चौपालों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

30 से 40 शिल्पियों को मिलेगा मौका हम हर बार मेले में अलग-अलग के शिल्पियों को स्टॉल उपलब्ध करवाते हैं। इस बार नए वर्ष में

30 से 40 शिल्पियों को मौका दिया जाएगा। हरियाणा के 10 और बाकी स्टाल राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और पश्चिम बंगाल के शिल्पियों को दिए जाएंगे। हमारा प्रयास है कि शिल्पी अपने हुनर से प्रदेश का नाम भी चमकाएं।

दोनों परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में हो रहा काम फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद (Faridabad-Noida-Ghaziabad) और पूर्व से पश्चिम फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को लेकर प्रशासन बेहद गंभीर दिखाई दे रहा है। दोनों परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इन दोनों परियोजनाओं पर करीब 2431 करोड़ रुपये की लागत आनी है।

फरीदाबाद व गुरुग्राम से अधिकतर लोग नोएडा की ओर आते हैं। फिलहाल यह स्थिति है कि गुरुग्राम से नोएडा के लिए करीब दो घंटे से अधिक तथा फरीदाबाद से नोएडा की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। ऐसे में आमजन को रोजाना सड़कों पर जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

परिवहन विशेष न्यूज

पलवल जिले के पुराने शहर में स्थानीय निवासी बूंद-बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। बीते 100 घंटे से शहर में पानी की सप्लाई ठप है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों के साथ ही छोटे बच्चों को भी हो रही है। 20 हजार से ज्यादा लोगों को पानी नहीं मिला। दुकानदार ने थोड़ी देर सबमर्सिबल पंप चलाकर लोगों को पानी भरने दिया।

पलवल। साहब! पीने का पानी तो मिल नहीं रहा है। शौचालय के लिए पानी कहाँ से लाएँ? घर में लोग शौचालय जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। यही नजारा पुराने शहर की ऊँची बसावट पर बसे मोहल्लों में देखने को मिला।

इन मोहल्लों में सबसे ज्यादा बुरी हालत बुजुर्गों व छोटे बच्चों को हो रही है। जिस भी गली में निकलो महिलाएँ, पुरुष आपस में घर में पीने के कारण हो रही समस्या को बता दिखे।

इन् मोहल्लों में सबसे ज्यादा बुरी हालत बुजुर्गों व छोटे बच्चों को हो रही है। जिस भी गली में निकलो महिलाएँ, पुरुष आपस में घर में पीने के कारण हो रही समस्या को बता दिखे।

पुराने शहर के 20 हजार से ज्यादा लोगों को नहीं मिला पानी इन मोहल्लों में चौथे दिन भी पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हुई। इससे शहर में शुक्रवार को



पानी के लिए हाहाकार मच गया। पुराने शहर के 20 हजार से ज्यादा लोगों को पानी की आपूर्ति नहीं हुई। एक-एक बाल्टी पानी के लिए लोगों को सबमर्सिबल पंप वाले घरों में कतार लगानी पड़ी। जिला उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ का दावा है कि शुक्रवार दोपहर बाद तक कुछ जगह आपूर्ति शुरू हो जाएगी।

दैनिक जागरण ने सुबह साढ़े छह बजे इन मोहल्लों का दौरा किया तो देखा कि जिस भी गली में जाओं सुबह-सुबह लोग बाल्टी लेकर पानी के लिए इधर-उधर भटकते मिले। मीनार गेट पर दुकान साढ़े छह बजे जमुना कचौड़ी वाले को सुकान खुली। वैसे ही खैल खुर्द, खैलकलां से महिलाएँ व पुरुष अपने हाथों में बाल्टियाँ, प्लास्टिक की बोतलें दुकान पर पहुंच गए।

दुकानदार ने थोड़ी देर सबमर्सिबल पंप चलाकर लोगों को पानी भरने दिया। उसके बाद दुकानदार ने पंप बंद कर दिया। कई महिलाओं को दुकान से पानी न मिलता देख मायूस होकर अपने घर की ओर रवाना हो गईं। मीनार गेट पर

ग्राहकों के लिए वाटर कूलर से भी महिलाओं ने पानी भरने की कोशिश की। मगर वाटर कूलर से भी दो तीन ही बोतल भरी गई। उसके बाद वाटर कूलर भी खाली हो गया।

एक-एक बाल्टी पानी के लिए लोगों को सबमर्सिबल वाले पड़ोसियों की मिन्नतें करनी पड़ीं। नीमतला, थाई मोहल्ला में महिलाएँ जैन मंदिर में लगे सबमर्सिबल पंप से पानी भरने पहुंचीं। उन्होंने बताया कि उनके घर में एक बूंद पानी नहीं है। इसलिए सुबह पांच बजे से ही मंदिर में पानी लेने आना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे भी पिछले तीन दिनों से बिना नहाए ही स्कूल जाने को मजबूर हैं।

सबमर्सिबल के सहारे लोग खैल खुर्द मोहल्ले में चार से पांच फुट चौड़ी गलियों में रहने वालों को चौथे दिन भी पानी नहीं मिला। लोगों को समतल मकानों में लगे सबमर्सिबल पंप से पानी भरने के लिए पूरी गली के लोगों को मिन्नतें करनी पड़ीं। तंग गली के कारण टैंकर अंदर आना मुमकिन नहीं। लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ा।

शहीद भगत सिंह के बलिदान पर क्यों उठ रहे सवाल

राज सदोष

किसी वक्त केन्द्रीय जेल का हिस्सा रहे शादमान चौक लाहौर का नामकरण शहीदे आजम भगत सिंह के नाम पर करने के लिए लंबे संघर्ष के बाद भगत सिंह मैमोरियल फाऊंडेशन लाहौर के पक्ष में उच्च न्यायालय ने आदेश तो जारी कर दिए लेकिन उसकी पालना करने की बजाय अवमानना का...

किसी वक्त केन्द्रीय जेल का हिस्सा रहे शादमान चौक लाहौर का नामकरण शहीदे आजम भगत सिंह के नाम पर करने के लिए लंबे संघर्ष के बाद भगत सिंह मैमोरियल फाऊंडेशन लाहौर के पक्ष में उच्च न्यायालय ने आदेश तो जारी कर दिए लेकिन उसकी पालना करने की बजाय अवमानना का सामना कर रहे लाहौर नगर निगम ने अब एक रिपोर्ट पेश की है जिसे किसी सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी द्वारा लिखा हुआ बताया है। इस रिपोर्ट में न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे विश्व में बहस को जन्म दिया है। भगत सिंह मैमोरियल फाऊंडेशन लाहौर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना-पहचाना नाम है। इसके अध्यक्ष इम्तियाज रशद कुरेशी ने तर्क दिया कि अविभाजित डूबहदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न समुदायों, विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। क्रांतिकारी आंदोलन के अलावा कई महत्वपूर्ण हस्तियों ने विदेशी दासता को समाप्त करने के लिए भी आंदोलन शुरू किए। इनमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, जिनकी बदीलत



पाकिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध देश के रूप में उभरा है। कुरेशी के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील जुलफारन चौक और मनवर हुसैन खोखर ने शादमान चौक नामकरण भगत सिंह के नाम पर करने के आदेश को रद्द करने वाले पंजाब सरकार के दस्तावेज के जवाब में कहा है कि पाकिस्तान की जनता अच्छी तरह जानती है कि ये सब इतिहास में दर्ज तथ्य हैं और हम इन्हें नकार नहीं सकते। हम इस तथ्य से भी इंकार नहीं कर सकते कि स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों के बलिदान ने ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी थी, जिनमें से पाकिस्तान में जन्मे भगत सिंह का नाम पूरी दुनिया जानती है और उनके विचारों को लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानती है।

कायदे आजम ने 1929 में सेंट्रल असेंबली दिल्ली में क्रांतिकारी युवाओं द्वारा किए गए विस्फोटों के बाद दिए भाषण में न केवल भगत सिंह और उनके साथियों के बलिदानों का नाम प्रशंसा की थी बल्कि मजबूत इरादे से उनके समर्थन में खड़े भी हुए और ब्रिटिश कानून व्यवस्था और सिद्धांतों पर सवाल उठाए। लाहौर हाईकोर्ट ने शादमान चौक को भगत सिंह चौक बनाने का फैसला दिया लेकिन नहीं बनाया गया। अदालत की अवमानना के सवाल पर पंजाब

सरकार के प्रतिनिधियों ने हाईकोर्ट को जो जवाब दिया, वह काफी हास्यास्पद, इतिहास से छेड़छाड़ और इस्लामी नजिए को तोड़-मरोड़कर पेश करने वाला है। सरकारी की ओर से हाईकोर्ट को ऐसा जवाब तब दिया गया, जब बीते शुक्रवार उन्हें अवमानना मामले में जवाब देने का आखिरी मौका दिया गया था।

फाऊंडेशन का कहना है कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी सपूत थे जो पाकिस्तान की धरती पर पैदा हुए। अब हम छत्र राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने देश के इतिहास को नष्ट नहीं होने दे सकते। शहीद भगत सिंह चौक के निर्माण के खिलाफ कोई ठोस रुख पेश करने के बजाय पंजाब सरकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पंजाब सरकार की ओर से सहायक महाधिवक्ता असगर लोघारी ने अपने जवाब में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है और उनका मानना है कि देश के संविधान और इतिहास की जांच किए बिना, उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों ने शादमान चौक का नाम शहीद भगत सिंह चौक रखने का फैसला दे दिया। पंजाब सरकार के अनुसार भगत सिंह को क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद नहीं थे, बल्कि आज की परिभाषा में एक अपराधी और आतंकवादी थे। फाऊंडेशन कहती है कि अगर ऐसा था तो कायदे आजम उनके बचाव में अपने विचार व्यक्त रखते। यहां यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में भगत सिंह के बारे में जो दृष्टिकोण कभी औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार का था, लगभग वही दृष्टिकोण वर्तमान पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों का भी है।

पंजाब सरकार पाकिस्तान में जन्मे महान क्रांतिकारी की स्मृति को संरक्षित करने की योजना को घृणित बता रही है। ऐसा करके वह लाहौर के इतिहास पर सवालिया निशान लगा

रही है और हर उस चीज के प्रति नफरत का संदेश भेज रही है जिसने आज के पाकिस्तान के क्षेत्र में इतिहास की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। लाहौर सेंट्रल जेल अपने आप में दुनिया के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पन्ना है क्योंकि भगत सिंह और उनके 2 साथियों को समय से पहले ही वहां फांसी दे दी गई थी।

फाऊंडेशन को आपत्ति है कि पंजाब सरकार ने तर्क दिया है कि 23 साल की उम्र में कोई क्रांतिकारी नहीं बनता। यह बयान बिल्कुल हास्यास्पद है। बहुत कम उम्र में कई क्रांतिकारी हुए हैं और कई धार्मिक हस्तियों ने भी बहुत कम उम्र में ज्ञान का प्रसार किया। फाऊंडेशन की याचिका को खारिज करवाने के लिए 16 पेज का उत्तर लिखने वाले सरकारी प्रतिनिधियों को इतिहास की जानकारी नहीं है। क्या फिलिस्तीन में युवा लड़ाकों को अपराधी कहा जा सकता है? जबकि इसराईली शासक उन्हें अपराधी और आतंकवादी मानते हैं।

पंजाब सरकार का कहना है कि भगत सिंह खुद को नास्तिक कहते थे और इस संदर्भ में उन्हें शहीद कहना उन्हें इस्लाम के लिए शहीदों के बराबर बताता है। यह अवधारणा पंजाब सरकार की देन है, भगत सिंह मैमोरियल फाऊंडेशन ने कभी ऐसी तुलना नहीं की। इस्लाम के संदेश पर चलकर मानवता की भलाई और शांति की राह पर कुर्बानी देना ही शाहादत है। भगत सिंह के लेख 'मैं नास्तिक क्यों हूँ' में साफ लिखा है कि हमारे समाज में जिस तरह का भेदभाव और अपराध है, वह धर्म के खिलाफ है। उस लेख का चौक का नामकरण नकारने के लिए बहाना बनाना गलत है, इसके लिए समाज में मौजूद व्यवस्था और शासक जिम्मेदार हैं। पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों को भगत सिंह के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने और समझने की जरूरत है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि भगत सिंह 2 समुदायों की सर्वोच्च शक्तियों के अनुयायी थे और दूसरी ओर उन्हें नास्तिक बता रही है।

गुरुग्राम के लोगों के लिए गुड न्यूज, 25 सेक्टरों में 24 घंटे होगी पेयजल आपूर्ति

गुरुग्राम वासियों को जल्द घरों में 24 पीने का पानी मिलेगा। पहले चरण में 25 सेक्टरों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति होगी। इसके लिए 563 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार हो गई है। पहले चरण में पुराने गुरुग्राम के सेक्टरों को इसका लाभ मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। अटल मिशन (अमृत) के तहत नगर निगम को बजट मिलेगा।

गुरुग्राम। साइबर सिटी के 25 सेक्टरों में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति होगी। इसके लिए पिछले दो साल से चल रही तैयारी में अब 563 करोड़ रुपये की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो गई है। डीपीआर को स्वीकृति के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग मुख्यालय को इस महीने के अंत तक भेज दिया जाएगा। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पुराने गुरुग्राम के सेक्टरों को इस योजना का लाभ मिलेगा। वर्ष 2025 यानी अगले साल इस प्रोजेक्ट के शुरू होने की उम्मीद है।

अमृत योजना के तहत नगर निगम को मिलेगा बजट खास बात यह है कि प्रोजेक्ट के लिए कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (अमृत) के तहत नगर निगम को बजट दिया जाएगा। शुरूआत में सिर्फ सात रिहायशी क्षेत्रों में 24 घंटे और सातों दिन पेयजल आपूर्ति देने की योजना थी, लेकिन अब डीपीआर में बदलाव कर इसके पहले चरण में 25 सेक्टरों को शामिल किया गया है।

इन सेक्टरों को मिलेगा 24 घंटे पानी निगम द्वारा तैयार की गई डीपीआर के अनुसार सेक्टर तीन ए, चार, पांच, छह, सात, नौ, दस, नौ, दस, दस ए, 11 ए, 12, 12 ए, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और सेक्टर 36 को पहले चरण में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति दी जाएगी। योजना के दूसरे चरण में 28 सेक्टर शामिल होंगे। इन सेक्टरों का योजना के तहत कुल



86.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर होगा। **लीकेज होगी बंद, नया नेटवर्क बिछेगा** 24 घंटे पेयजल आपूर्ति के लिए नगर निगम को अपना पेयजल आपूर्ति नेटवर्क हाइड्रक बनाना होगा। लगभग 30 से 35 साल पहले बिछाई गई पुरानी पानी की लाइनों को बदलकर नई लाइनें बिछाई जाएंगी ताकि लाइनों की लीकेज से होने वाली पानी की बर्बादी को रोका जा सके। शहर में घरों तक पेयजल आपूर्ति नगर निगम और बूरिस्टिंग स्टेशनों तक आपूर्ति जोएमडीए करता है।

सभी कनेक्शनों पर लगेगी मीटर शहर में पानी के कनेक्शनों पर मीटर लगाए जाएंगे ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। फिलहाल ज्यादातर कनेक्शनों पर मीटर नहीं लगे हैं और निगम अपने उपभोक्ताओं से पानी के बिलों की रिकवरी नहीं कर पा रहा है। जोएमडीए ने पिछले दिनों नगर निगम को 117 करोड़ रुपये का पानी का बिल भेजा था।

फिलहाल यह है स्थिति

- नहरी पेयजल आपूर्ति : 570 एमएलडी
- बसई और चंदू बुढ़ेड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता : 570 एमएलडी
- शहर में पानी की मांग : 550 एमएलडी
- मई-जून में पानी मांग पहुंच जाती है : 660 एमएलडी से ऊपर
- शहर की आबादी : लगभग 30 लाख
- नगर निगम क्षेत्र में कुल पेयजल कनेक्शन : 2.10 लाख

-सौजन्य:-

ईवी ड्राइव द फ्यूचर



ईवी कंपनियों और बैटरी निर्माताओं ने ट्रम्प से वाहन कर क्रेडिट को खत्म न करने का किया आग्रह

परिवहन विशेष न्यूज

टेस्ला और एलजी सहित इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी दिग्गजों के गठबंधन ने राष्ट्रपति-चुनाव ट्रम्प से इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन और बिक्री के लिए कर प्रोत्साहन बनाए रखने की अपील की है। उनका तर्क है कि इन क्रेडिट ने प्रमुख राज्यों में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया है और उन्हें खत्म करने से आर्थिक विकास में बाधा आएगी और मौजूदा निवेश कमजोर पड़ेगा।

प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ने शुक्रवार, 15 नवंबर को राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प से इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री और उत्पादन के लिए कर क्रेडिट को खत्म न करने का आग्रह किया, जिसमें

रिपब्लिकन के लिए मतदान करने वाले प्रमुख राज्यों पर प्रभाव का हवाला दिया गया।

जीरो एमिशन ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन जिसके सदस्यों में रिवियन एलजी, टेस्ला, उबर, ल्यूसिड और पैनासोनिक शामिल हैं ने कहा कि उत्पादन कर क्रेडिट ने ओहियो, केंटकी, मिशिगन और जॉर्जिया जैसे राज्यों में भारी रोजगार पैदा किया है और चेतावनी दी है कि उन उत्पादन और उपभोग कर क्रेडिट को खत्म करने से उन निवेशों में कमी आएगी और अमेरिकी रोजगार वृद्धि को नुकसान होगा।

रॉयटर्स ने गुरुवार, 14 नवंबर को सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि ट्रम्प ट्रान्जिशन टीम इलेक्ट्रिक-वाहन खरीद के लिए \$ 7,500 उपभोक्ता कार क्रेडिट को खत्म करना चाहती है।



बायोगैस निकाय ने कहा, लोगों को स्वच्छ ईंधन, ईवी की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऑड/ईवन नियम लागू करें

संजय बाटला

भारतीय बायोगैस एसोसिएशन ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन या संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) या प्राकृतिक गैस पर आधारित वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली एनसीआर में चार पहिया वाहनों के लिए सम-विषम नियम लागू करने का सुझाव दिया है।

मेडेडरिस्पॉस एक्शन प्लान (जीआरएपी) 4 (वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से अधिक) के तहत, चार पहिया वाहनों के लिए सम/विषम नियम लागू किया गया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने वायु गुणवत्ता के रंगीन श्रेणी में बने रहने के कारण पहले ही प्रेप 3 उपाय लागू कर दिए हैं।

भारतीय बायोगैस एसोसिएशन (आईबीई) के अध्यक्ष गौरव केडिया ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा, "हम आने वाले महीनों में पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए सम-विषम नियम लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर पर अच्छा प्रभाव देखा जा सके, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों और सीएनजी/सीबीजी वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए क्योंकि इससे नागरिक हरित ईंधन विकल्पों की ओर रुख करने के लिए बाध्य होंगे।

दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति हर सर्दियों में खराब हो जाती है, मौसमी वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार 300 अंक से ऊपर रहता है। अपने गंभीर रूप से प्रदूषित AQI के कारण दिल्ली ने दुनिया भर का ध्यान पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहरों में से एक के रूप में आकर्षित किया है।



पड़ोसी राज्यों में फसल अवशेषों, विशेषकर धान के पुआल को जलाना, इस परिदृश्य में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, लेकिन यह बड़ी पहली का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। केडिया ने सुझाव दिया कि सरकार को प्रोत्साहन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे बिजली बिलों पर कम शुल्क, पीएनजी कनेक्शन, तथा जैविक कचरे को प्रभावी ढंग से अलग करने वाले घरों के लिए एलपीजी सिलेंडर।

उन्होंने कहा कि इससे दोहरा लाभ होगा: बायोगैस संयंत्रों के लिए एकत्रित हरे और पत्तेदार कचरे को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन होगा तथा लैंडफिल लोड में उल्लेखनीय कमी आएगी।

उन्होंने कहा कि आगामी बजट में अगले पांच वर्षों में दिल्ली के कम से कम 85 प्रतिशत कचरे को अलग करने और प्रसंस्करण करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि

उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

दिल्ली में जैविक कचरा प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है, जो लैंडफिल को भरता है। ये अतिप्रवाहित स्थल लगातार जल रहे हैं, जिससे जहरीला धुआं और मीथेन गैस की महत्वपूर्ण मात्रा निकल रही है, जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है।

2023-2024 में दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 11,342 टन कचरा उत्पन्न होगा। SWM (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) नियम, 2016 के कार्यान्वयन पर 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, उत्पन्न MSW (नगरपालिका ठोस अपशिष्ट) का 33.5 प्रतिशत लैंडफिल में जाता है, लेकिन एसोसिएशन के अनुमान के अनुसार यह संख्या लगभग 35 प्रतिशत है।

उत्पादित सभी नगरपालिका ठोस अपशिष्टों में से लगभग 40-60 प्रतिशत जैविक

प्रकृति के होते हैं। यह बायोगैस उत्पादन के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अप्रयुक्त संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है।

केडिया ने कहा कि इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि कोई भी जैविक अपशिष्ट लैंडफिल साइटों तक न पहुंचे, बल्कि उसे ऊर्जा उत्पन्न करने वाले बायो-मीथेनेशन संयंत्रों में डाला जाना चाहिए।

शहर में पहले से ही 4 अपशिष्ट-से-ऊर्जा सुविधाएं संचालित हैं, जिनकी संयोजी प्रसंस्करण क्षमता 6,550 टन प्रतिदिन है।

शहर में पाँच बायो-गैस प्लांट हैं जो सामूहिक रूप से प्रतिदिन 7 टन कचरे का उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा 5 टीपीडी क्षमता वाले आठ बायो-मीथेनेशन प्लांट भी हैं, लेकिन ये प्लांट काम नहीं कर रहे हैं।

केडिया ने यह भी सुझाव दिया कि देश को बायो-पीएनजी से चलने वाले जनरेटर को अपनाया जाए क्योंकि वे स्वच्छ ईंधन हैं। उन्होंने बताया कि आंशिक बायो-पीएनजी उपयोग क्षमता वाले डीजल जनरेटर को फिर से लगाना या उन्हें पूरी तरह से बायो-पीएनजी से बदलना हानिकारक उत्सर्जन को कम करने में काफी मददगार साबित होगा।

दिल्ली सरकार का 2024-25 के लिए कुल बजट ₹ 71,086 करोड़ है, जिसमें से ₹ 858.5 करोड़ वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और हरित स्थानों को मजबूत करने के लिए आवंटित किए गए हैं।

यह आवंटन शहर के वार्षिक बजट का लगभग 1.21 प्रतिशत है, जो 2020-21 में मात्र 0.08 प्रतिशत से उल्लेखनीय वृद्धि है, जो 65,000 करोड़ रुपये के कुल बजट पर 52 करोड़ रुपये था।

सीसीपीए उत्पाद मानकों और सेवा को लेकर ओला इलेक्ट्रिक की जांच करेगी: रिपोर्ट



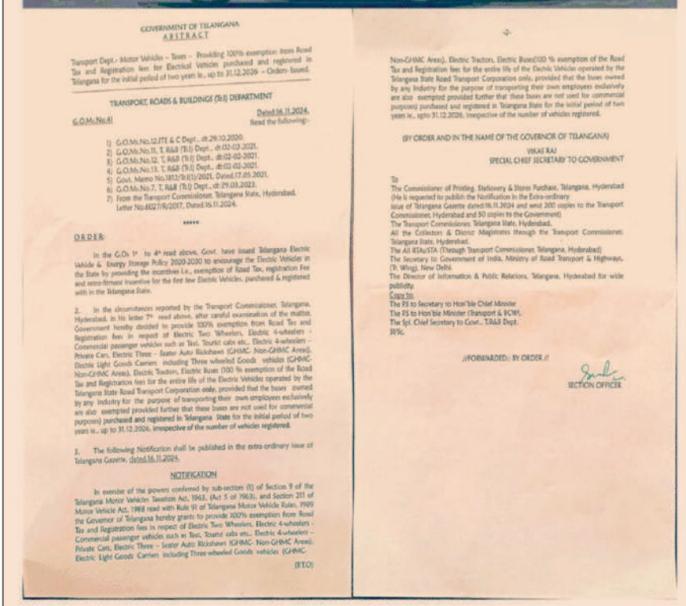
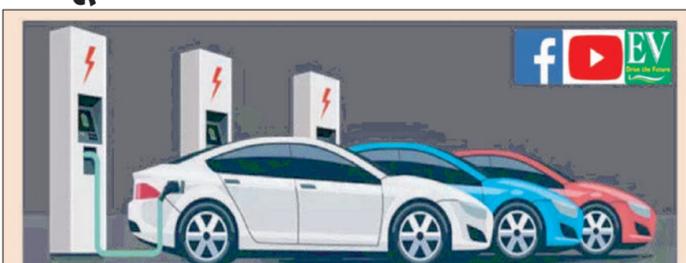
परिवहन विशेष न्यूज

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, भारत की उत्पाद प्रमाणन एजेंसी, ओला इलेक्ट्रिक के मानकों की कमी और उत्पाद-संबंधी मुद्दों की जांच करेगी, उपभोक्ता मामलों के सचिव ने 14 नवंबर, 2024 को रॉयटर्स को बताया।

अखबार ने बताया कि पिछले महीने सीसीपीए ने 10,000 शिकायतों मिलने के बाद स्पष्टीकरण मांगते हुए ई-स्कूटर निर्माता को नोटिस भेजा था। न्यूजवायर न्यूज के अनुसार, ओला ने कहा कि उसने 99.1% शिकायतों का समाधान कर दिया है। उस प्रतिक्रिया की समीक्षा करने

के बाद, सीसीपीए ने भारतीय मानक ब्यूरो से मामले की विस्तार से जांच करने को कहा है। इस मुद्दे पर रॉयटर्स को ओला इलेक्ट्रिक से समय पर जवाब नहीं मिल सका। अगस्त में शानदर लिस्टिंग के बाद बढ़ती शिकायतों और नियामक जांच ने ओला इलेक्ट्रिक को मुश्किल में डाल दिया है।

तेलंगाना सरकार ने कर, पंजीकरण छूट के साथ पेश की नई ईवी नीति



परिवहन विशेष न्यूज

लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास में तेलंगाना सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से 100 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है। नई ईवी नीति सोमवार, 18 नवंबर से लागू होगी।

रिवार, 17 नवंबर को मीडिया से बात करते हुए परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि नई नीति से तेलंगाना में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा दक्षता के राज्य के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क माफ़ी के साथ-साथ सरकारी बुनियादी ढांचे में सुधार करने की योजना बना रही है, जिसमें अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन और निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

यह छूट इलेक्ट्रिक दोपहिया, चार पहिया, वाणिज्यिक यात्री वाहनों जैसे टैक्सि, तीन सीटर ऑटोरिक्षा और इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स कैरियर (तीन पहिया माल वाहन वाहन सहित), ट्रेक्टर

और बसों पर लागू होगी। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ किसी भी उद्योग द्वारा अपने कर्मचारियों को विशेष रूप से परिवहन करने के लिए स्वामित्व वाली बसों (वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं की जाने वाली) के पूरे जीवनकाल के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से पूरी तरह छूट होगी। छूट शुरू में 31 दिसंबर, 2026 तक दो साल के लिए वैध होगी, चाहे पंजीकृत वाहनों की संख्या कुछ भी हो।

तेलंगाना में 31 दिसंबर, 2026 तक के शुरुआती दो वर्षों के लिए खरीदी और पंजीकृत की गई इलेक्ट्रिक बसों को भी, पंजीकृत वाहनों की संख्या की परवाह किए बिना, ईवी के पूरे जीवनकाल के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है, लेकिन इनका संचालन केवल तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा ही किया जाना चाहिए। किसी भी उद्योग द्वारा अपने कर्मचारियों को विशेष रूप से परिवहन के उद्देश्य से स्वामित्व वाली बसों को भी छूट दी गई है, बशर्ते कि इन बसों का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए न किया जाए।

इलेक्ट्रिक कारों के मामले में भारत चीन से पीछे

परिवहन विशेष न्यूज

चीन में ग्रीन एनर्जी वाहनों का दबदबा है और इस साल चीन ने 10 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का लक्ष्य पार करके इतिहास रच दिया है। चीनी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की हैं, जिनमें सब्सिडी, टैक्स में छूट और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष लेन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन नीतियों ने न केवल उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया है बल्कि निर्माताओं को भी बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया है।

चीनी ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स फेडरेशन से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार, 14 नवंबर को चीन में नए ऊर्जा वाहनों यानी इलेक्ट्रिक वाहनों का वार्षिक उत्पादन पहली बार 10 मिलियन से अधिक हो गया है। चीन दुनिया का



पहला ऐसा देश बन गया है, जिसका नए ऊर्जा वाहनों का वार्षिक उत्पादन 10 मिलियन से अधिक है।

आंकड़ों की मानें तो चीन ने वर्ष 2013 में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री को

सांख्यिकी प्रणाली में शामिल किया था। उस वर्ष उत्पादन केवल 18 हजार था। वर्ष 2018 तक चीन में नए ऊर्जा वाहनों का उत्पादन 10 लाख तक पहुंच गया और फिर वर्ष 2022 तक यह 50 लाख तक पहुंच गया। अनुमान है कि इस वर्ष नए

ऊर्जा वाहनों का उत्पादन 1 करोड़ 20 लाख से अधिक होगा।

पिछले 10 वर्षों में चीनी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को विकसित करने के लिए सौ से अधिक उदार नीतियों को लागू किया है। चीन के नए ऊर्जा वाहन व्यवसाय के विकास में बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। भविष्य में चीन उत्पादन और बिक्री के साथ-साथ गुणवत्ता भी बढ़ाएगा ताकि वह विश्व के नए ऊर्जा व्यवसाय में योगदान दे सके।

चीन में कई बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियां हैं, जो बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करती हैं। इन कंपनियों ने बैटरी तकनीक, मोटर डिजाइन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया है। इसके कारण चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें लगातार कम हो रही हैं और उनकी बैटरी रेंज और प्रदर्शन में भी सुधार हो रहा है।

ओईएम ने पीएम ई-ड्राइव के तहत ई-ट्रक सब्सिडी के प्रभावी उपयोग के लिए घटक प्रोत्साहन का दिया प्रस्ताव

परिवहन विशेष न्यूज

भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित एक परामर्श बैठक के दौरान टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड सहित भारतीय ट्रक निर्माताओं ने इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए 500 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए घटक-स्तरीय प्रोत्साहन और दीर्घकालिक परिसंपत्ति उपयोग की वकालत की। मूल उपकरण निर्माताओं यानी के नेताओं ने सरकार से उद्योग को सहायता प्रदान करने के साधन के रूप में विशेष रूप से उच्च प्रभाव वाले ग्राहक-संचालित क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्ति उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित एक परामर्श बैठक के दौरान जिसमें नीति आयोग, एसआईएमए और सड़क परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ओईएम के प्रतिनिधियों ने वाहन-स्तरीय प्रोत्साहनों के अलावा घटक-स्तरीय प्रोत्साहनों पर विचार करने का भी सुझाव दिया।

इसके अलावा वे सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत हुए कि ट्रक विद्युतीकरण के शुरुआती चरण में स्थापित मार्गों और पूर्वानुमानित उपयोग पैटर्न पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अशोक लेलैंड में विनियामक मामलों और उत्पाद समरूपता के प्रमुख मुख्युक्तामर पुन ने बड़े ट्रकों के लिए परिचालन की कुल लागत में कमी लाने के लिए ई-कॉम्पस जैसे उच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों को लक्षित करने के महत्व पर जोर दिया, जो वर्तमान में पारंपरिक ईंधन पर चल रहे हैं।



वर्तमान में टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक ट्रकों के सबसे व्यापक चयन के साथ बाजार में अग्रणी हैं।

टाटा मोटर्स के वाणिज्यिक वाहन कारोबार के लिए रणनीति प्रमुख प्रसाद फड़के ने सब्सिडी निधि की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए स्थायी परिसंपत्ति उपयोग की पहचान करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

इसके अलावा महिंद्रा ट्रक और बस डिवाइजन में होमोलोगेशन के प्रमुख वीजी कुलकर्णी सहित विशेषज्ञों ने महिंद्रा के ई-ट्रकों के बारे में जानकारी दी और वाहन-स्तरीय प्रोत्साहनों के साथ-साथ घटक-स्तरीय प्रोत्साहनों के महत्व को रेखांकित किया। मुरारामा ग्रुप, टीआईएन मोबिलिटी के कार्यपरेट रिश्तास के वरिष्ठ भागीदार एसओ त्यागी ने कहा कि ई-ट्रकों को प्रोत्साहित करने से भारत में उनके विकास और अपनाने में तेजी आएगी।

उपस्थित अन्य उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि देश का लगभग 18% प्रदूषण भारी परिवहन क्षेत्र से उत्पन्न होता है, जिससे पता चलता है कि स्वच्छ परिवहन नेटवर्क बनाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक ट्रक भारत के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे महंगे ईंधन आयात को कम करते हैं और शहरी वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त ये वाहन देश के जलवायु उद्देश्यों के अनुरूप हैं, जो डीजल ट्रकों के लिए एक टिकाऊ विकल्प प्रदान करते हैं।

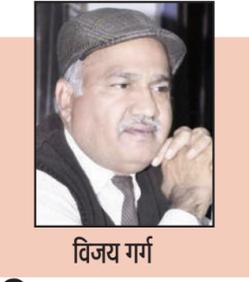
विशेषज्ञों ने आगे कहा कि पीएम ई-ड्राइव योजना टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए। सरकार का सब्सिडी कार्यक्रम नवाचार को बढ़ावा देने और अधिक ट्रक ओईएम के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक उत्पादन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है, जिससे अल्ट्रावीथ में ईंधन की खपत में संभावित 27% की कमी और 2030 तक 40% की कमी जैसे तत्काल लाभ हो सकते हैं। ऐसी सब्सिडी आंतरिक दहन इंजन ट्रकों और इलेक्ट्रिक विकल्पों के बीच 3x से 4x मूल्य अंतर को पाटने में मदद कर सकती है।

मांग सृजन के मोर्चे पर अमेजन इंडिया के सार्वजनिक नीति प्रबंधक निखिल देहिया ने एक

मजबूत ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। ओईएम प्रतिनिधियों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि एक व्यापक राष्ट्रव्यापी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति, विशेष रूप से माल बुलाई मार्गों पर क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रकों को आमतौर पर 100 किलोवाट से अधिक उच्च-शक्ति वाले चार्ज की आवश्यकता होती है, यदि अधिक निर्माताओं को इलेक्ट्रिक ट्रकों में निवेश करना शुरू करना है।

कार्यक्रम में विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भारत के ग्रिड के संरेखण पर चर्चा की तथा कहा कि वितरण ग्रिड अवसंरचना, ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार बिजली कटौती के कारण राजमार्गों पर अविश्वसनीय विद्युत गुणवत्ता से ग्रस्त है। एमएचआई के सचिव कामरान रिजवी ने कहा, ईई-ट्रक चरण अभी शुरू हुआ है और भारत वैश्विक स्तर पर ई-ट्रक बनाने वाले 5-6 देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि 2070 तक नेट जीरो के लिए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, रनिमाताओं, खरीदारों और बैंकों को एक साथ आना चाहिए ताकि तेज और सुचारु बदलाव सुनिश्चित हो सके।

पीएम ई ड्राइव कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए सब्सिडी योजना के क्रियान्वयन के लिए हिस्से के रूप में, भारत सरकार हरियाच्यव के लिए टिकाऊ परिवहन समाधान को बढ़ावा देने के लिए शिपर्स, लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं और उद्योग जगत के नेताओं सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है।



विजय गर्ग

डिजिटल मीडिया नैतिकता डिजिटल समाचार मीडिया की विशिष्ट नैतिक समस्याओं, प्रथाओं और मानदंडों से संबंधित है। डिजिटल समाचार मीडिया में ऑनलाइन पत्रकारिता, ब्लॉगिंग, डिजिटल फोटो पत्रकारिता, नागरिक पत्रकारिता और सोशल मीडिया शामिल हैं। इसमें यह प्रश्न शामिल हैं कि पेशेवर पत्रकारिता को कहानियों पर शोध और प्रकाशन करने के लिए इस 'नए मीडिया' का उपयोग कैसे करना चाहिए, साथ ही नागरिकों द्वारा प्रदान किए गए पाठ या छवियों का उपयोग कैसे करना चाहिए। नैतिकता में एक क्रांति मीडिया क्रांति, मौलिक रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से, पत्रकारिता की प्रकृति और इसकी नैतिकता को बदल रही है। प्रकाशन का साधन अब नागरिकों के हाथ में है, जबकि इंटरनेट पत्रकारिता के नए रूपों को प्रोत्साहित करता है जो इंटीग्रेटेड और तत्काल हैं। हमारी मीडिया परिस्थितिकी एक अराजक परिदृश्य है जो तीव्र गति से विकसित हो रही है। पेशेवर पत्रकार पत्रकारिता क्षेत्र को ट्वीटर, ब्लॉगिंग, नागरिक पत्रकारों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करते हैं। प्रत्येक क्रांति के बीच, नई संभावनाएँ उभरती हैं जबकि पुरानी प्रथाएँ खतरे में पड़ जाती हैं। आज कोई अपवाद नहीं है। दर्शकों के ऑनलाइन प्रवास के कारण पेशेवर पत्रकारिता का अर्थशास्त्र संघर्ष कर रहा है। समाचार कक्षों का सिकुड़ना पत्रकारिता के भविष्य के लिए चिंता पैदा करता है। फिर भी ये डर पत्रकारिता में खोजी पत्रकारिता के गैर-लाभकारी केंद्रों जैसे प्रयोगों को भी प्रेरित करते हैं। एक केंद्रीय प्रश्न यह है कि मौजूदा मीडिया नैतिकता आज और कल के समाचार मीडिया के लिए किस हद तक उपयुक्त है? जो तत्काल, इंटरैक्टिव और रहमशा चालू है - शौकीनों और पेशेवरों की पत्रकारिता। अधिकांश सिद्धांत पिछली सदी में विकसित किए गए थे, जिनकी उर्वरति 19वीं सदी के अंत में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक समाचार पत्रों के लिए पेशेवर, वस्तुनिष्ठ नैतिकता के निर्माण में हुई थी। हम एक मिश्रित समाचार मीडिया की ओर बढ़ रहे हैं - एक समाचार मीडिया नागरिक और कई मीडिया प्लेटफार्मों पर पेशेवर पत्रकारिता। इस नए मिश्रित समाचार मीडिया को नई मिश्रित मीडिया नैतिकता की आवश्यकता है - दिशानिर्देश जो शौकिया और पेशेवर पर लागू होते हैं, चाहे वे ब्लॉग, ट्वीट, प्रसारण या समाचार पत्रों के लिए लिखते हों। मीडिया की नैतिकता पर पुराने जमाने की नहीं, बल्कि आज की मीडिया के लिए पुनर्विचार और पुनर्निर्माण की जरूरत है। दो स्तरों पर तनाव ये बदलाव मीडिया नैतिकता की नींव को चुनौती देते हैं। चुनौती किसी एक या किसी अन्य सिद्धांत, जैसे वस्तुनिष्ठता, के बारे में बहस से कहीं अधिक गहरी है। चुनौती विशिष्ट समस्याओं से कहीं अधिक बड़ी है, जैसे कि समाचार कक्ष नागरिकों की सामग्री को कैसे सहायित कर सकते हैं। क्रांति के लिए हमें प्रथाओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एक ऐसे पेशे के लिए नैतिकता का क्या मतलब हो सकता है जिसे तुरंत समाचार और विश्लेषण प्रदान करना चाहिए; जहां मॉडेम वाला हर व्यक्ति प्रकाशक है? मीडिया क्रांति ने दो स्तरों पर नैतिक तनाव पैदा कर दिया है। पहले स्तर पर, पारंपरिक पत्रकारिता और ऑनलाइन पत्रकारिता के

बीच तनाव है। पारंपरिक पत्रकारिता की संस्कृति, सटीकता, पूर्व-प्रकाशन सत्यापन, संतुलन, निष्पक्षता और गेट-कीपिंग के मूल्यों के साथ, ऑनलाइन पत्रकारिता की संस्कृति के खिलाफ है जो तात्कालिकता, पारदर्शिता, पक्षपात, गैर-पेशेवर पत्रकारों और प्रकाशन के बाद पर जोर देती है। सुधार। दूसरे स्तर पर, संकीर्ण और वैश्विक पत्रकारिता के बीच तनाव है। यदि पत्रकारिता का प्रभाव वैश्विक है, तो इसकी वैश्विक जिम्मेदारियाँ क्या हैं? क्या मीडिया नैतिकता को अपने लक्ष्यों और मानदंडों में सुधार करना चाहिए ताकि उन पत्रकारिता का मार्गदर्शन किया जा सके जो अब पहुंच और प्रभाव में वैश्विक है? वो कैसा लगता है? आज की मीडिया नैतिकता के लिए चुनौती को इस प्रश्न से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: मल्टी-मीडिया, वैश्विक पत्रकारिता की दुनिया में नैतिकता कहां है? मीडिया नैतिकता को इन तनावों को उजागर करने के अलावा और भी बहुत कुछ करना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से, यह होना ही चाहिए-मूल्यों के बीच संघर्ष को सुलझाएं। उसे यह तय करना होगा कि किन सिद्धांतों को संरक्षित या आविष्कार किया जाना चाहिए। व्यावहारिक रूप से, इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन पत्रकारिता का मार्गदर्शन करने के लिए नए मानक प्रदान करने चाहिए। स्तरित पत्रकारिता एक एकीकृत नैतिकता कैसे दिखेगी? यह एकीकृत न्यूज़रूम की नैतिकता होगी, एक ऐसा न्यूज़रूम जो स्तरित पत्रकारिता का अभ्यास करता है। स्तरित पत्रकारिता नागरिक पत्रकारिता और इंटीग्रेटेड चैट के साथमिलकर पेशेवर शैली के समाचारों की विश्लेषण की एक मल्टी-मीडिया पेशकश नहीं है। दर्शकों के ऑनलाइन प्रवास के कारण पेशेवर पत्रकारिता का अर्थशास्त्र संघर्ष कर रहा है। समाचार कक्षों का सिकुड़ना पत्रकारिता के भविष्य के लिए चिंता पैदा करता है। फिर भी ये डर पत्रकारिता में खोजी पत्रकारिता के गैर-लाभकारी केंद्रों जैसे प्रयोगों को भी प्रेरित करते हैं। एक केंद्रीय प्रश्न यह है कि मौजूदा मीडिया नैतिकता आज और कल के समाचार मीडिया के लिए किस हद तक उपयुक्त है? जो तत्काल, इंटरैक्टिव और रहमशा चालू है - शौकीनों और पेशेवरों की पत्रकारिता। अधिकांश सिद्धांत पिछली सदी में विकसित किए गए थे, जिनकी उर्वरति 19वीं सदी के अंत में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक समाचार पत्रों के लिए पेशेवर, वस्तुनिष्ठ नैतिकता के निर्माण में हुई थी। निर्माता होंगे जिन पर पड़ोस में जाकर नगरिकों को अपनी कहानियाँ बनाने के लिए मीडिया का उपयोग करने में मदद करने का आरोप लगाया जाएगा। क्षैतिज रूप से, भविष्य का न्यूज़रूम फ्रंट और प्रसारण अनुभागों से लेकर ऑनलाइन उत्पादन केंद्रों तक, पत्रकारिता के प्रकार के आधार पर स्तरित होगा। अतीत में समाचार कक्षों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज परतें होती थीं। अखबारों के समाचार कक्ष शीर्ष पर प्रधान संपादक से लेकर नीचे शावक के रिपोर्टर तक लंबवत रूप से फैले हुए हैं। क्षैतिज रूप से, बड़े मुख्यधारा के समाचार कक्षों ने फ्रंट और प्रसारण दोनों, कई प्रकार की पत्रकारिता का उत्पादन किया है। हालाँकि, भविष्य के न्यूज़रूम में अतिरिक्त और अलग-अलग परतें होंगी। कुछ समाचार साइटें ब्लॉगिंग जैसे केवल एक प्रारूप के लिए समर्पित कुछ लोगों द्वारा संचालित होती रहेंगी। लेकिन नई मुख्यधारा के एक बड़े हिस्से में ये जटिल, स्तरित संगठन शामिल होंगे। स्तरित पत्रकारिता को दो प्रकार की समझनाओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले, इस बारे में 'ऊर्ध्वाधर' नैतिक प्रश्न होंगे कि पेशेवर संपादकों से लेकर नागरिक प्रौद्योगिकी तक, न्यूज़रूम की विभिन्न

परतों को जिम्मेदार पत्रकारिता का उत्पादन करने के लिए कैसे बातचीत करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, पेशेवर संपादक नागरिक पत्रकारों के योगदान का मूल्यांकन किस मानक से करेंगे? दूसरा, विभिन्न न्यूज़रूम अनुभागों के मानदंडों के बारे में 'क्षैतिज' प्रश्न होंगे। डिजिटल मीडिया नैतिकता के लिए कठिन प्रश्न पत्रकार कौन है? मीडिया का 'लोकतांत्रिकीकरण' - प्रौद्योगिकी जो नागरिकों को पत्रकारिता और कई प्रकार के प्रकाशनों में शामिल होने की अनुमति देती है - पत्रकारों की पहचान और पत्रकारिता के गठन के विचार को धुंधला कर देती है। पिछली सदी में पत्रकार एक स्पष्ट रूप से परिभाषित समूह थे। अधिकांश भाग वे पेशेवर थे जिन्होंने प्रमुख मुख्यधारा के समाचार पत्रों और प्रसारकों के लिए लिखा था। जनता को रेप्रेसर के सदस्यों को पहचानने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं हुई। आज, पत्रकारिता प्रशिक्षण के बिना नागरिक और जो मुख्यधारा के मीडिया के लिए काम नहीं करते हैं, वे खुद को पत्रकार कहते हैं, या ऐसे तरीके से जो पत्रकारों या आविष्कार किया जाना चाहिए। व्यावहारिक रूप से, इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन पत्रकारिता का मार्गदर्शन करने के लिए नए मानक प्रदान करने चाहिए। स्तरित पत्रकारिता एक एकीकृत नैतिकता कैसे दिखेगी? यह एकीकृत न्यूज़रूम की नैतिकता होगी, एक ऐसा न्यूज़रूम जो स्तरित पत्रकारिता का अभ्यास करता है। स्तरित पत्रकारिता नागरिक पत्रकारिता और इंटीग्रेटेड चैट के साथमिलकर पेशेवर शैली के समाचारों की विश्लेषण की एक मल्टी-मीडिया पेशकश नहीं है। दर्शकों के ऑनलाइन प्रवास के कारण पेशेवर पत्रकारिता का अर्थशास्त्र संघर्ष कर रहा है। समाचार कक्षों का सिकुड़ना पत्रकारिता के भविष्य के लिए चिंता पैदा करता है। फिर भी ये डर पत्रकारिता में खोजी पत्रकारिता के गैर-लाभकारी केंद्रों जैसे प्रयोगों को भी प्रेरित करते हैं। एक केंद्रीय प्रश्न यह है कि मौजूदा मीडिया नैतिकता आज और कल के समाचार मीडिया के लिए किस हद तक उपयुक्त है? जो तत्काल, इंटरैक्टिव और रहमशा चालू है - शौकीनों और पेशेवरों की पत्रकारिता। अधिकांश सिद्धांत पिछली सदी में विकसित किए गए थे, जिनकी उर्वरति 19वीं सदी के अंत में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक समाचार पत्रों के लिए पेशेवर, वस्तुनिष्ठ नैतिकता के निर्माण में हुई थी। निर्माता होंगे जिन पर पड़ोस में जाकर नगरिकों को अपनी कहानियाँ बनाने के लिए मीडिया का उपयोग करने में मदद करने का आरोप लगाया जाएगा। क्षैतिज रूप से, भविष्य का न्यूज़रूम फ्रंट और प्रसारण अनुभागों से लेकर ऑनलाइन उत्पादन केंद्रों तक, पत्रकारिता के प्रकार के आधार पर स्तरित होगा। अतीत में समाचार कक्षों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज परतें होती थीं। अखबारों के समाचार कक्ष शीर्ष पर प्रधान संपादक से लेकर नीचे शावक के रिपोर्टर तक लंबवत रूप से फैले हुए हैं। क्षैतिज रूप से, बड़े मुख्यधारा के समाचार कक्षों ने फ्रंट और प्रसारण दोनों, कई प्रकार की पत्रकारिता का उत्पादन किया है। हालाँकि, भविष्य के न्यूज़रूम में अतिरिक्त और अलग-अलग परतें होंगी। कुछ समाचार साइटें ब्लॉगिंग जैसे केवल एक प्रारूप के लिए समर्पित कुछ लोगों द्वारा संचालित होती रहेंगी। लेकिन नई मुख्यधारा के एक बड़े हिस्से में ये जटिल, स्तरित संगठन शामिल होंगे। स्तरित पत्रकारिता को दो प्रकार की समझनाओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले, इस बारे में 'ऊर्ध्वाधर' नैतिक प्रश्न होंगे कि पेशेवर संपादकों से लेकर नागरिक प्रौद्योगिकी तक, न्यूज़रूम की विभिन्न

प्रौद्योगिकी के साथ सुविधा, संस्थान कैसे काम करते हैं इसका ज्ञान और अत्यधिक विकसित संचार कौशल शामिल हैं। नैतिक मानदंडों में सटीकता, सत्यापन, सत्य आदि के प्रति प्रतिबद्धता शामिल हैं। मानक दृष्टिकोण जनता को सटीक और जिम्मेदारी से सूचित करने वाली पत्रकारिता के आदर्श दृष्टिकोण पर आधारित है। पत्रकारिता के सर्वोत्तम उदाहरणों और सर्वोत्तम पत्रकारों की कार्यप्रणाली पर विचार करके पत्रकारिता को परिभाषित किया जाता है। एक लेखक जिसके पास ये कौशल और ये नैतिक प्रतिबद्धताएँ हैं, वह अच्छी (अच्छी तरह से तैयारी की गई, अच्छी तरह से शोध की गई) और नैतिक रूप से जिम्मेदार पत्रकारिता प्रकाशित करने में सक्षम है। जो व्यक्ति इन मानक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं वे स्वयं को पत्रकार कह सकते हैं लेकिन इस मानक दृष्टिकोण से उन्हें पत्रकार नहीं माना जाता है। वे गैरजिम्मेदार, दोषम दजें के या अक्षम लेखक हैं जो पत्रकार बनना नहीं हैं, या पत्रकार होने का दिखावा करते हैं। गुमनामी मुख्यधारा के समाचार मीडिया की तुलना में गुमनामी को ऑनलाइन अधिक आसानी से स्वीकार किया जाता है। समाचार पत्रों को आमतौर पर संपादक को प्र लिखने वालों से अपनी पहचान बताने की आवश्यकता होती है। मुख्यधारा की मीडिया नैतिकता के कोड पत्रकारों को गुमनाम स्रोतों का संयम से उपयोग करने का चेतावनी देते हैं और केवल तभी जब पत्रकार 2 यदि हास्य अभिनेता जॉन स्टीवर्ट खुद को पत्रकार कहने से इनकार करते हैं, लेकिन पत्रकारों उन्हें एक प्रभावशाली पत्रकार के रूप में संदर्भित करती हैं (या उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में संदर्भित करती हैं जो पत्रकारिता में संलग्न हैं) तो क्या स्टीवर्ट एक पत्रकार हैं? क्या फेसबुक साइट पर अपनी राय व्यक्त करने वाला व्यक्ति पत्रकार है? पत्रकारिता क्या है? पत्रकार कौन है, इस पर स्पष्टता की कमी के कारण पत्रकारिता को अपनी स्वीकार है, इस पर निश्चित विवाद पैदा होता है। इससे यह प्रश्न उठता है: पत्रकारिता क्या है? बहुत से लोग मानते हैं, रपत्रकारिता क्या है? र या विनमति टिप्पणीकार होंगे। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के संपादक भी होंगे। कुछ संपादक इन नए पत्रकारों के साथ काम करेंगे, जबकि अन्य संपादक नागरिकों द्वारा इमेल, वेब साइटों और ट्विटर के माध्यम से भेजी गई अवांछित छवियों और पाठ से निपटेंगे। ऐसे संपादक या रसायुद्युतिक निर्माता होंगे जिन पर पड़ोस में जाकर नगरिकों को अपनी कहानियाँ बनाने के लिए मीडिया का उपयोग करने में मदद करने का आरोप लगाया जाएगा। क्षैतिज रूप से, भविष्य का न्यूज़रूम फ्रंट और प्रसारण अनुभागों से लेकर ऑनलाइन उत्पादन केंद्रों तक, पत्रकारिता के प्रकार के आधार पर स्तरित होगा। अतीत में समाचार कक्षों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज परतें होती थीं। अखबारों के समाचार कक्ष शीर्ष पर प्रधान संपादक से लेकर नीचे शावक के रिपोर्टर तक लंबवत रूप से फैले हुए हैं। क्षैतिज रूप से, बड़े मुख्यधारा के समाचार कक्षों ने फ्रंट और प्रसारण दोनों, कई प्रकार की पत्रकारिता का उत्पादन किया है। हालाँकि, भविष्य के न्यूज़रूम में अतिरिक्त और अलग-अलग परतें होंगी। कुछ समाचार साइटें ब्लॉगिंग जैसे केवल एक प्रारूप के लिए समर्पित कुछ लोगों द्वारा संचालित होती रहेंगी। लेकिन नई मुख्यधारा के एक बड़े हिस्से में ये जटिल, स्तरित संगठन शामिल होंगे। स्तरित पत्रकारिता को दो प्रकार की समझनाओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले, इस बारे में 'ऊर्ध्वाधर' नैतिक प्रश्न होंगे कि पेशेवर संपादकों से लेकर नागरिक प्रौद्योगिकी तक, न्यूज़रूम की विभिन्न

परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हाल ही में 'मंदि' हुई काम करते हैं इसका ज्ञान और अत्यधिक विकसित संचार कौशल शामिल हैं। नैतिक मानदंडों में सटीकता, सत्यापन, सत्य आदि के प्रति प्रतिबद्धता शामिल हैं। मानक दृष्टिकोण जनता को सटीक और जिम्मेदारी से सूचित करने वाली पत्रकारिता के आदर्श दृष्टिकोण पर आधारित है। पत्रकारिता के सर्वोत्तम उदाहरणों और सर्वोत्तम पत्रकारों की कार्यप्रणाली पर विचार करके पत्रकारिता को परिभाषित किया जाता है। एक लेखक जिसके पास ये कौशल और ये नैतिक प्रतिबद्धताएँ हैं, वह अच्छी (अच्छी तरह से तैयारी की गई, अच्छी तरह से शोध की गई) और नैतिक रूप से जिम्मेदार पत्रकारिता प्रकाशित करने में सक्षम है। जो व्यक्ति इन मानक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं वे स्वयं को पत्रकार कह सकते हैं लेकिन इस मानक दृष्टिकोण से उन्हें पत्रकार नहीं माना जाता है। वे गैरजिम्मेदार, दोषम दजें के या अक्षम लेखक हैं जो पत्रकार बनना नहीं हैं, या पत्रकार होने का दिखावा करते हैं। गुमनामी मुख्यधारा के समाचार मीडिया की तुलना में गुमनामी को ऑनलाइन अधिक आसानी से स्वीकार किया जाता है। समाचार पत्रों को आमतौर पर संपादक को प्र लिखने वालों से अपनी पहचान बताने की आवश्यकता होती है। मुख्यधारा की मीडिया नैतिकता के कोड पत्रकारों को गुमनाम स्रोतों का संयम से उपयोग करने का चेतावनी देते हैं और केवल तभी जब पत्रकार 2 यदि हास्य अभिनेता जॉन स्टीवर्ट खुद को पत्रकार कहने से इनकार करते हैं, लेकिन पत्रकारों उन्हें एक प्रभावशाली पत्रकार के रूप में संदर्भित करती हैं (या उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में संदर्भित करती हैं जो पत्रकारिता में संलग्न हैं) तो क्या स्टीवर्ट एक पत्रकार हैं? क्या फेसबुक साइट पर अपनी राय व्यक्त करने वाला व्यक्ति पत्रकार है? पत्रकारिता क्या है? पत्रकार कौन है, इस पर स्पष्टता की कमी के कारण पत्रकारिता को अपनी स्वीकार है, इस पर निश्चित विवाद पैदा होता है। इससे यह प्रश्न उठता है: पत्रकारिता क्या है? बहुत से लोग मानते हैं, रपत्रकारिता क्या है? र या विनमति टिप्पणीकार होंगे। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के संपादक भी होंगे। कुछ संपादक इन नए पत्रकारों के साथ काम करेंगे, जबकि अन्य संपादक नागरिकों द्वारा इमेल, वेब साइटों और ट्विटर के माध्यम से भेजी गई अवांछित छवियों और पाठ से निपटेंगे। ऐसे संपादक या रसायुद्युतिक निर्माता होंगे जिन पर पड़ोस में जाकर नगरिकों को अपनी कहानियाँ बनाने के लिए मीडिया का उपयोग करने में मदद करने का आरोप लगाया जाएगा। क्षैतिज रूप से, भविष्य का न्यूज़रूम फ्रंट और प्रसारण अनुभागों से लेकर ऑनलाइन उत्पादन केंद्रों तक, पत्रकारिता के प्रकार के आधार पर स्तरित होगा। अतीत में समाचार कक्षों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज परतें होती थीं। अखबारों के समाचार कक्ष शीर्ष पर प्रधान संपादक से लेकर नीचे शावक के रिपोर्टर तक लंबवत रूप से फैले हुए हैं। क्षैतिज रूप से, बड़े मुख्यधारा के समाचार कक्षों ने फ्रंट और प्रसारण दोनों, कई प्रकार की पत्रकारिता का उत्पादन किया है। हालाँकि, भविष्य के न्यूज़रूम में अतिरिक्त और अलग-अलग परतें होंगी। कुछ समाचार साइटें ब्लॉगिंग जैसे केवल एक प्रारूप के लिए समर्पित कुछ लोगों द्वारा संचालित होती रहेंगी। लेकिन नई मुख्यधारा के एक बड़े हिस्से में ये जटिल, स्तरित संगठन शामिल होंगे। स्तरित पत्रकारिता को दो प्रकार की समझनाओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले, इस बारे में 'ऊर्ध्वाधर' नैतिक प्रश्न होंगे कि पेशेवर संपादकों से लेकर नागरिक प्रौद्योगिकी तक, न्यूज़रूम की विभिन्न

करते हैं - जैसे किसी पत्रकार को हितों के टकराव या आंशिक टिप्पणी के लिए निर्लंबित करना - वे पूर्ण सार्वजनिक सभ्यता प्राप्त करने में विफल रहते हैं। कुछ नागरिक और समूह पत्रकारिता के बीच खल-दू, समाचार कार्यक्रमों और ब्रेकिंग स्टोरीज के बारे में 'लाइव' ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अनिवार्य रूप से, जब कोई इस गति से काम करता है, तो जूटियाँ होती हैं, शब्दों की गलत वर्तनी से लेकर तथ्यात्मक त्रुटियाँ तक। क्या समाचार संगठनों को वापस जाना चाहिए और उन सभी गलतियों को सुधारना चाहिए उन सामग्री के पहाड़ों को सुधारना करती हैं? या क्या उन्हें बाद में त्रुटियों को सुधारना चाहिए और मूल जलती का कोई निशान नहीं छोड़ना चाहिए - जिसे अग्रकाशित करना कठिन कहा जाता है? नैतिक चुनौती ऑनलाइन दुनिया में अफवाहों से निपटने और सुधार के लिए दिशानिर्देश तैयार करना है जो सटीकता, सत्यापन और पारदर्शिता के सिद्धांतों के अनुरूप हों। निष्पक्षता, हितों का टकराव और पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता न्यू मीडिया लोगों को अपनी राय व्यक्त करने और अपने विचार व्यक्त कर साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कई लोगों किसी भी मुख्यधारा के पत्रकारों की तुलना में अपने मन की बात कहने में गर्व महसूस करते हैं, जिन्हें घटनाओं को निष्पक्ष रूप से पत्रकार करना होता है। कई ऑनलाइन पत्रकार स्वयं को राजनीतिक आंदोलनों के पक्षधर या कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं, और वस्तुनिष्ठ या तटस्थ विश्लेषण के विचार को अस्वीकार करते हैं। आंशिक या पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता कम से कम दो प्रकार की होती है: एक प्रकार की ओपिनियन पत्रकारिता है जिसमें घटनाओं और मुद्दों पर सत्यापन के साथ या बिना सत्यापन के टिप्पणी करने का आनंद मिलता है। दूसरा रूप पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता है जो मीडिया को राजनीतिक दलों और आंदोलनों के मुखपत्र के रूप में उपयोग के लिए गंभीर रूप से तैयार है और फिर शीर्ष पर संपादक के इस नए क्षेत्र के साथ/पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता का पुनरुद्धार मीडिया स्वयं का खंडन करता है जब वे ऑनलाइन गुमनामी की अनुमति देते हैं लेकिन अनिश्चितता पर और प्रसारण कार्यक्रमों में गुमनामी से इनकार करते हैं। नैतिक प्रश्न: गुमनामी नैतिक रूप से कब स्वीकार्य है और क्या मीडिया के लिए विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के लिए गुमनामी पर अलग-अलग नियम लागू करना असंगत है? ऑफलाइन और ऑनलाइन गुमनामी के लिए नैतिक दिशानिर्देश क्या होने चाहिए? गति, अफवाह और सुधार रिपोर्ट और छवियाँ ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, ब्लॉग, सेल फोन और ईमेल के माध्यम से अद्भुत गति से दुनिया भर में प्रसारित होती हैं। स्पष्ट न्यूज़रूम पर कहानियों को प्रकाशित रूप से जांच और सत्यापन कर ले। प्रमुख समाचार संगठन भी अक्सर ऑनलाइन अफवाहें उठाते हैं। कभी-कभी, ऑनलाइन अफवाह प्रकाशित करने का प्रभाव दुनिया को हिला देने वाला नहीं होता - एक झूठी रिपोर्ट कि एक हॉकी कोच को निकाल दिया गया है। लेकिन एक मीडिया जो गति और रसायनकरण पर पनपता है वह बड़े नुकसान की संभावना पैदा करता है। उदाहरण के लिए, समाचार संगठन झूठी अफवाह को दोहराने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं कि आतंकवादियों ने लंदन भूमिगत पर नियंत्रण कर लिया है, कि एक

न्यूज़रूम की वेबसाइट संचालित करने वाले पत्रकार अपने सहयोगियों, फ्रंट पत्रकारों के सामने किसी कहानी पर रिपोर्ट कर सकते हैं? दूसरे शब्दों में, क्या फ्रंट पत्रकारों को प्रकाशन-पूर्व सत्यापन के उच्च मानक पर रखा जाना चाहिए? इसके अलावा, जैसे-जैसे न्यूज़रूम के कर्मचारी कम होते जा रहे हैं, और ऑनलाइन समाचारों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, संगठन आपदाओं, दुर्घटनाओं और अथवा ब्रेकिंग न्यूज़ को कवर करने में नागरिकों के साथ सहयोग करने में सक्षम और इच्छुक रूप से सूचित करने का प्रयास करते हैं, बल्कि जनता की राय को प्रभावित करने वाले समूहों का हिस्सा बन जाते हैं? नैतिक चुनौती यह है कि उस मीडिया के लिए जनहित में स्वतंत्र पत्रकारिता का क्या मतलब है, जहां कोई नए प्रकार की पत्रकारिता सामने आ रही है और जहां विनोदी सिद्धांतों को चुनौती दी जा रही है। उद्यमशील गैर-लाभकारी पत्रकारिता नागरिकों के ऑनलाइन प्रवास के कारण मुख्यधारा मीडिया के पाठकों और मुनाफे में गिरावट के कारण समाचार कक्षों में अपने कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है। कुछ पत्रकार विज्ञापन और प्रसार विप्रेरी पर आधारित जनसंचार माध्यम के पुराने आर्थिक मॉडल की निरंतर व्यवहार्यता पर संदेह करते हैं। जवाब में, कई पत्रकारों ने फाउंडेशनों के पैसे और नागरिकों से मिले दान के आधार पर गैर-लाभकारी समाचार कक्ष, समाचार वेब साइटें और खोजी पत्रकारिता केंद्र शुरू किए हैं। कुछ पत्रकार ऑनलाइन जाते हैं और नागरिकों से स्टोरीज करने के लिए ऐसे भेजने के लिए कहते हैं। इस प्रवृत्ति को रजदमी पत्रकारिता कहा जा सकता है क्योंकि अग्रकाशित अवकेलरिपोर्ट नहीं करता है बल्कि पत्रकारों (जैसे विज्ञापन कर्मचारी) अपने न्यूज़रूम के लिए धन जुटाते हैं। ये पत्रकार उद्यमी हैं जो अपने नए उद्यमों के लिए धन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। नए उद्यम नैतिक प्रश्न उठाते हैं। ऐसे न्यूज़रूम कितने स्वतंत्र हो सकते हैं जब वे सीमित संख्या में दानदाताओं से मिलने वाले धन पर निर्भर हैं? यदि न्यूज़रूम अपने मुख्य वित्तपोषकों में से किसी एक के बारे में नकारात्मक कमेंटारि रिपोर्टें प्रकाशित करते हैं, तो क्या होगा? ये न्यूज़रूम किससे पैसा लेंगे? वे इस बारे में कितने पारदर्शी होंगे कि उन्हें पैसा कौन देता है और किस शर्तों पर? पत्रकारिता के इस नए क्षेत्र के लिए एक नैतिकता का निर्माण करना चुनौती है। पत्रकार सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं कि इस समाचार संगठन अपने संवाददाताओं को जानकारी इकट्ठा करने और आसानी ब्लॉग, फेसबुक पेज या ट्विटर अकाउंट शुरू करके अपने लिए एक रजिस्टर्ड बनाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हालाँकि, ऑनलाइन टिप्पणीकार पत्रकारों, विशेष रूप से बीट पत्रकारों को उनके संपादकों या उन लोगों के साथ परेशानी में डाल सकता है जिनके बारे में वे टिप्पणी करते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता का अर्थ पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता? मामले को और अधिक विवादस्पद बनाने के लिए, राय और निष्पक्ष पत्रकारिता के कुछ नए प्रतिपादक न केवल निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, वे लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांत पर भी सवाल उठाते हैं कि पत्रकारों को उन समूहों से स्वतंत्र होना चाहिए जिनके बारे में वे लिखते हैं। उदाहरण विश्वसनीयता के बारे में पर्याप्त रूप से जांच और सत्यापन कर ले। प्रमुख समाचार संगठन भी अक्सर ऑनलाइन अफवाहें उठाते हैं। कभी-कभी, ऑनलाइन अफवाह प्रकाशित करने का प्रभाव दुनिया को हिला देने वाला नहीं होता - एक झूठी रिपोर्ट कि एक हॉकी कोच को निकाल दिया गया है। लेकिन एक मीडिया जो गति और रसायनकरण पर पनपता है वह बड़े नुकसान की संभावना पैदा करता है। उदाहरण के लिए, समाचार संगठन झूठी अफवाह को दोहराने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं कि आतंकवादियों ने लंदन भूमिगत पर नियंत्रण कर लिया है, कि एक

बुखार शरीर के लिए क्यों अच्छा है

बुखार भले ही तकलीफदेह हो, लेकिन यह हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली में अहम भूमिका निभाता है। बेशक, बुखार की निगरानी करना और अगर यह बहुत ज्यादा या लगातार बना रहे तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। यह आपके शरीर का लड़ाई के लिए तैयार होने और यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि आप दूसरी तरफ मचबूत होकर बाहर आए बुखार को अक्सर शरीर के लिए एक बुरा दौर माना जाता है क्योंकि यह हमें असह्य, सुस्त और कमजोर महसूस कराता है। क्या आप जानते हैं कि बुखार वास्तव में हमारे शरीर के रक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जबकि उच्च बुखार की निगरानी और प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है, निचले स्पेक्ट्रम (99.1 डिग्री फारेनहाइट से 102 डिग्री फारेनहाइट तक) पर बुखार कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है **बुखार वास्तव में आपके लिए अच्छा क्यों हो सकता है।** श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ता है जब हमें बुखार होता है, तो हमारा शरीर श्वेत रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ा देता है। ये कोशिकाएँ हमारी प्रतिक्रिया प्रणाली के अग्रिम पंक्ति के सैनिक हैं, जो बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोगजनकों की पहचान करने और उन पर हमला करने के लिए जिम्मेदार हैं। जर्नल इम्यूनोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, शरीर का बढ़ा हुआ तापमान अस्थि मज्जा को अधिक श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित

करता है, जिससे हमारे शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। यह बढ़ा हुआ उत्पादन हमारी प्रतिक्रिया प्रणाली को आक्रमणकारियों के प्रति अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है, जिससे बीमारी की गंभीरता और अवधि कम हो जाती है। **बैक्टीरिया और वायरस की वृद्धि को धीमा करता है** बुखार बैक्टीरिया और वायरस के पनपने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाता है। कई रोगणु शरीर के सामान्य तापमान 37C (98.6F) को पसंद करते हैं। जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है, तो यह इन सूक्ष्मजीवों की प्रतिकृति को धीमा कर सकता है। जर्नल ऑफ वायरोलॉजी के शोध से पता चला है कि उच्च शरीर का तापमान कुछ वायरस, जैसे कि

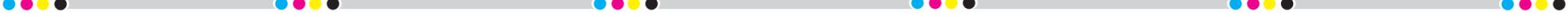
इन्फ्लूएंजा वायरस की प्रतिकृति को बाधित कर सकता है। उनकी वृद्धि को धीमा करने से हमारी प्रतिक्रिया प्रणाली को प्रभावी बचाव करने और प्रतिकृति को खत्म करने के लिए अधिक समय मिलता है। **एंटीवायरल और जीवाणुरोधी गतिविधि में सुधार** शरीर का उच्च तापमान न केवल रोगजनकों को धीमा करता है बल्कि कुछ प्रतिक्रिया कोशिकाओं की गतिविधि को भी बढ़ाता है। बुखार साइटोकिन्स नामक प्रोटीन के उत्पादन को बढ़ाता है, जो प्रतिक्रिया प्रतिक्रियाओं को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये साइटोकिन्स, बदले में, आपके शरीर के भीतर एंटीवायरल और जीवाणुरोधी अणुओं की गतिविधि को बढ़ाते हैं।

दिल्ली दुनिया के नक्शे पर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक होने का है रान कर देने वाला दार्ज प्रान्त चर चुकी है। प्रदूषण क्यों होता है? इस सवाल का पता लगाने के लिए शासन और प्रशासन डटे हुए हैं। विशेषज्ञ और वैज्ञानिक जो भी कहते रहे लेकिन दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सांस लेना भारी हो रहा है। सारी दिल्ली गैस का चैबर बन चुकी है। यकार क्वालिटि इंडेक्स अर्थात वायु गुणवत्ता का लेवल 400 पार हो चुका है। इसीलिए इस कड़ी में दो दिन पहले जब पांचवी कक्षा तक के बच्चों के स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया तो हर कोई है रान रह गया लेकिन बच्चों को स्वस्थ बनाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं। इसके साथ ही उनकी पढ़ाई-लिखाई अब ऑनलाइन की जायेगी यह जानकारी दिल्ली में प्रदूषण अब विनाशकारी असर दिखाने लगा है। में सीधा बच्चों पर केंद्रित होना चाहती हूँ और पांचवी कक्षा तक के बच्चों के ऑनलाइन जुड़ने को लेकर थोड़ी संतुष्ट इसलिए हूँ कि उन्हें प्रदूषण से बचा लिया जायेगा लेकिन साथ ही चिंता की बात यह है कि बच्चों के मानसिक विकास का यह तरीका बचपन की एक मौज-मस्ती की स्टेज को प्रभावित जरूर करेगा। ऑनलाइन स्टीडी एक सुरक्षित तरीका हो सकता है लेकिन इसके व्यावहारिक पहलू और जमीन कुछ अलग ही कहानी कहती है। बड़े-बड़े और आइवेट स्कूलों में पांचवी तक के बच्चों के पास मोबाइल नहीं होते लेकिन ऑनलाइन स्टीडी का मतलब है उनके लिए मोबाइल अनिवार्य कर देना। जो मोबाइल हमारे बचपन की मासूमियत छीन चुका है ऐसे में उन बच्चों का मोबाइल से कई-कई घंटे जुड़ना थोड़ा सा है रान करने वाली स्थिति जरूर है। प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए माता-पिता मोबाइल की व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए मां-बाप मोबाइल की व्यवस्था कैसे करेंगे और फिर प्रश्न यह भी है कि बच्चे मोबाइल को महज मनोरंजन के लिए प्रयोग करेंगे या फिर स्टीडी के लिए गंभीर भी होंगे, यह एक बड़ा प्रश्न है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि छोटे बच्चों के लिए प्रदूषण से बचाने की चिंता तो की जा रही है तो क्या छोटी से लेकर 12वीं के बच्चों पर प्रदूषण का असर नहीं

शिक्षा और बच्चे...

पड़ता लेकिन इस मामले में मेरा जवाब यह है कि छोटी उम्र के बच्चों को प्रदूषण से बचना बहुत जरूरी है। प्रदूषण के क्या कारण हैं, क्यों नहीं यह काम शासन, प्रशासन और विशेषज्ञ जानें लेकिन केवल पराली जलाना ही प्रदूषण फैलाने का बड़ा कारण नहीं। व्यक्तिगत तौर पर मैंने महसूस किया है कि सड़कों पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें और जिस रफात से व्हील आगे बढ़ते हैं वे बड़ी तेजी से खतरनाक गैसों भी छोड़ते हैं। ऐसा उत्सर्जन प्रदूषण फैलाने का एक बड़ा कारण है और इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। डीजल चालित वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर ग्रेप-3 के तहत अब पाबंदी लगा दी गयी है। यह कैसी व्यवस्था है कि महंगे वाहनों के चलने पर पाबंदी लग रही है, यह सवाल भी सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं लेकिन डीजल या अन्य वाहन उत्सर्जन तो एक जैसा ही करते हैं। दिल्ली के एक-एक घर में कई-कई वाहन बताए जाते हैं और वाहनों के चलाए जाने पर या सड़कों पर उतरने को लेकर ठोस व्यवस्था है या नहीं। हालाँकि ऑड-ईवन लागू भी किया गया था। शुरूआती दिनों में यह प्रयोग सफल भी रहा लेकिन जब सड़कों पर सैकड़ों की जगह हजारों और हजारों की जगह लाखों वाहन एक साथ उतरेंगे तो फिर खुद ही अंदाजा लगाइये गैस उत्सर्जन क्या करेगा? पांचवी कक्षा तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई उनके जीवन में तनाव ला सकती है। मनोरंजन पक्ष हावी रहेगा या शराबें तथा फिर गंभीरतापूर्वक स्टीडी होगी। इस सवाल का जवाब सोशल मीडिया पर मांगा जा रहा है। दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए खुद ही फैसला करना होगा। कुछ काम साईंकेलों से या सार्वजनिक वाहनों से या वाहन शेरों का करके भी किये जा सकते हैं। उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि सड़कों पर ज्यादा वाहन न हो लेकिन अब स्थिति बिगड़ चुकी है और वाहनों के गैस उत्सर्जन को भी कंट्रोल करना होगा, और भी उपाय करने होंगे। देखा है कि हर साल की तरह नवंबर में होने वाले प्रदूषण से दिल्ली वालों को मुक्ति कैसे मिलती है।

छोटे बच्चों का जैसे मिट्टी में खेलना जरूरी है, वैसे ही कक्षा में जाकर पढ़ना भी जरूरी है। क्योंकि बच्चे बहुत कुछ सिखते हैं। आपसी सहयोग, कर्मीटेशन, नई बातें, एजेंट्समेंट सभी कुछ स्कूल से सिखते हैं और जीवन का बेस बनते हैं तो सब मिलकर इसका समाधान हूँ। **विजय गर्ग**



अदानी टोटल गैस के इस एलान के बाद लग सकता है एक और महंगाई का झटका, बढ़ सकते हैं सीएनजी और पीएनजी के दाम

परिवहन विशेष न्यूज

अदानी टोटल गैस (Adani Total Gas) ने गैल इंडिया (GAIL-India) से गैस सप्लाई में 13 फीसदी कटौती का एलान किया है। इस एलान के बाद सीएनजी और पीएनजी की कीमतों (CNG-PNG Price) में तेजी आ सकती है। हालांकि कंपनी के इस फैसले के का असर शायर पर भी देखने को मिल सकता है। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव करने के कारण गाड़ीचालक को उम्मीद है कि जल्द ही पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती हो सकती है। लेकिन, अब CNG और PNG की कीमतों को लेकर बड़ा अपडेट आया है।

अदानी ग्रुप (Adani Group) की गैस कंपनी अदानी टोटल गैस (Adani Total Gas) ने गैल इंडिया (GAIL-India) से गैस सप्लाई में 13 फीसदी कटौती का एलान किया है। यह कटौती शनिवार से लागू हो गया है। इस एलान के बाद CNG और PNG की कीमतों में तेजी आ सकती है।

क्यों की गैस कटौती अदानी टोटल गैस ने कहा कि इसका असर कंपनी के प्रॉफिट पर उलटा पड़ सकता है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार प्रॉफिटबिलिटी की कमी पूरे CGD (सिटी गैस



महंगा हो सकता है CNG-PNG

डिस्ट्रीब्यूशन) इंडस्ट्री में है। इसके लिए कंपनी स्ट्रेकहोल्डर्स के साथ चर्चा कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी के मुनाफे पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इस साल अक्टूबर में अदानी टोटल गैस ने 16 फीसदी की कटौती की थी। यह कंपनी द्वारा दूसरी कटौती की गई। वर्तमान में अदानी टोटल गैस CGD के बिजनेस में कदम रखने की कोशिश कर रही है। बता दें कि अदानी टोटल गैस घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और

व्हीकल यूजर्स के लिए नैचुरल गैस (Natural Gas) सप्लाई करता है। सोमवार को शायर पर दिखेगा असर पिछले कारोबारी सत्र में BSE पर अदानी टोटल गैस के शेयर 0.75 फीसदी की तेजी के साथ 684.15 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ था। बीएसई की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन (Adani Total Gas M-Cap) 75,243.51 करोड़ रुपये है।

कंपनी द्वारा हाल ही में किए गए एलान के बाद सोमवार को शेयरों में गिरावट देखने को मिल सकती है। सोमवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों जैसे इंड्रप्रथ गैस, महानगर गैस और अदानी टोटल गैस के शेयर पर फोकस रहेगा। हाल ही में तीनों कंपनियों ने गैल इंडिया लिमिटेड से डोमेस्टिक गैस एलोकेशन में 13 से 20 फीसदी की कटौती करने का फैसला लिया था। इसके बाद सोमवार को इन कंपनियों के शेयर में फोकस रहेगा।

बिकवाली भरे कारोबार में दो कंपनियों के एम-कैप में हुई बढ़त, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले कुछ हफ्तों से स्टॉक मार्केट में बिकवाली भरा कारोबार देखने को मिला है। इस हफ्ते भी बाजार में बिकवाली जारी रही। इस बिकवाली भरे कारोबार के कारण शेयर बाजार के टॉप-10 फर्म में से 8 कंपनियों के संयुक्त एम-कैप में 1.65 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई। सबसे ज्यादा नुकसान HDFC Bank और SBI को हुआ।

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते शेयर बाजार में केवल 4 दिन ही कारोबार हुआ था। 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती के कारण स्टॉक मार्केट में छुट्टी थी। छोटे कारोबारी हफ्ते में शेयर बाजार में बिकवाली भरा कारोबार रहा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार स्टॉक मार्केट की टॉप-10 फर्म में से 8 कंपनियों के संयुक्त एम-कैप में 1.65 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है। इस हफ्ते एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम-कैप में भारी गिरावट आई थी। हालांकि, इन्फोसिस और टीसीएस के एम-कैप में तेजी आई।

अजीत मिश्रा - एसवीपी, रिसर्च, रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के अनुसार अक्टूबर में महंगाई दर आरबीआई के दायरे से पार हो गई



है। इसके साथ ही निराशाजनक तिमाही नतीजे जारी होने के कारण भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है।

किस कंपनी के एम-कैप में कितनी गिरावट

● एचडीएफसी बैंक का मूल्यांकन 46,729.51 करोड़ रुपये की गिरावट के साथ 12,94,025.23 करोड़ रुपये हो गया।

● इस हफ्ते भारतीय स्टेट बैंक का एम-कैप 34,984.51 करोड़ रुपये घट गया। अब बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,17,584.07 करोड़ रुपये है।

● हिंदुस्तान यूनिटीवर का बाजार पूंजीकरण 27,830.91 करोड़ रुपये घटकर 5,61,329.10 करोड़ रुपये हो गया।

● देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का 22,057.77 करोड़ रुपये कम होकर 17,15,498.91 करोड़ रुपये रह गया।

● आईटीसी का एमकैप

15,449.47 करोड़ रुपये गिरकर 5,82,764.02 करोड़ रुपये हो गया।

● भारती एयरटेल का बाजार पूंजीकरण 11,215.87 करोड़ रुपये घटकर 8,82,808.73 करोड़ रुपये रह गया।

● भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का बाजार मूल्यांकन 4,079.62 करोड़ रुपये घटकर 5,74,499.54 करोड़ रुपये है।

● आईसीआईआई बैंक का बाजार मूल्यांकन 2,832.38 करोड़ रुपये घटकर 8,85,599.68 करोड़ रुपये रह गया।

ऊपर लिखी कंपनियों के एम-कैप में आई गिरावट के बाजूद दो कंपनियों के एम-कैप में बढ़त हुई है। इन्फोसिस का एमकैप 13,681.37 करोड़ रुपये बढ़कर 7,73,962.50 करोड़ रुपये हो गया। इसके साथ ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का मार्केट कैप 416.08 करोड़ रुपये बढ़कर 15,00,113.36 करोड़ रुपये हो गया।

क्रेडिट कार्ड बीमा से खुद को और कार्ड को करें सिक्क्योर, फायदे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

आज के समय में इंश्योरेंस केवल आपके और फैमिली के लिए ही जरूरी नहीं है। बल्कि अब यह आपके क्रेडिट कार्ड के लिए भी जरूरी हो गया है। अब आप अपने क्रेडिट कार्ड का भी इंश्योरेंस करावा सकते हैं। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस का फायदा क्या है। यहां पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली। आज के समय में क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से पेमेंट करते समय एक डर बना रहता है कि कहीं कोई हमारा डेटा चोरी तो नहीं कर रहा है। ऐसे में अब आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक्सट्रा सिक्क्योर कर सकते हैं। जी हां, आप अपने क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस (Credit Card Insurance) करावा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस कैसे फायदेमंद है।

क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस क्या है? (What is Credit Card Insurance) क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस में आपको एक फिक्सड अमाउंट का प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। इस प्रीमियम

की पेमेंट के बाद आपके क्रेडिट कार्ड का इंश्योरेंस होगा। यह इंश्योरेंस आपके कार्ड को फाइनेंशियल नुकसान से बचाता है।

क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस के फायदे शॉपिंग में करता है मदद इस इंश्योरेंस में खरीदी गई वस्तु को भी कवर मिलता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपने कोई सामान खरीदा है और वह टूटा या खराब निकलता है तो इंश्योरेंस के तहत क्लेम कर सकते हैं।

ट्रैवल इंश्योरेंस का लाभ कई इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस में ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) को भी शामिल करती है। इसमें ट्रैवल के समय दुर्घटना होने या फिर चोरी होने की स्थिति में सिक्क्योरिटी देता है।

निश्चित होते हैं यूजर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड (Debit Card) के इंश्योरेंस हो जाने पर मानसिक शांति मिलती है। दरअसल, यह फाइनेंशियल सिक्क्योरिटी देता है।

फ्रॉड से बचाता कई इंश्योरेंस भी साइबर फ्रॉड से बचाने में मदद करता है।

दरअसल, अगर कोई आपका कार्ड चोरी करेगा है या फिर किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है तो इस इंश्योरेंस के तहत आप नुकसान के लिए क्लेम कर सकते हैं।

गलत ट्रॉजैक्शन पर रोक आज से समय में कई बार जल्दबाजी में गलत ट्रॉजैक्शन कर दिया जाता है। इस इंश्योरेंस में अवैध लेनदेन पर रोक लगाने की सर्विस उपलब्ध है। इस इंश्योरेंस के लेने के बाद कोई भी बिना यूजर के परमिशन के ट्रॉजैक्शन नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो एडवांस सिक्क्योरिटी के तहत ऑटोमैटिकली ट्रॉजैक्शन रोक दिया जाता है।

आपको बता दें कि इस इंश्योरेंस के तहत आप अपने बाकी संपत्ति जैसे लैपटॉप, मोबाइल आदि को भी सिक्क्योरिटी दे सकते हैं।

ये सुविधाएं भी है मौजूद अगर कभी आपका कार्ड खो या चोरी हो जाता है तो आप इस इंश्योरेंस में रिफ्लेसमेंट करवा भी मिलता है। इसके अलावा इंश्योरेंस में कई इमरजेंसी सर्विस भी उपलब्ध है। इसमें मेंडिकल, कानूनी और यात्रा संबंधी सहायता भी उपलब्ध करता है।

संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और सिंगापुर से सस्ता है भारत में सोना, क्यों अचानक आई इतनी बड़ी गिरावट?

परिवहन विशेष न्यूज

अक्टूबर में सोने की कीमतों में शानदार उछाल आया था। पिछले महीने सोने की कीमत रिकॉर्ड हाई पहुंच गया था। लेकिन नवंबर में सोने की कीमतों में 7 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। आज के समय में UAE कतर ओमान और सिंगापुर की तुलना में भारत में सस्ता सोना मिल रहा है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि सोने की कीमतों में क्यों गिरावट आई।

नई दिल्ली। भारत में कुछ समय से सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले महीने फेब्रिचर सोन के समय सोने और चांदी की कीमतों में शानदार तेजी आई थी। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि वेडिंग सीजन के समय में मांग के बढ़ जाने के कारण सोने की कीमतों में भी तेजी जारी रहेगी। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। कई कारणों से सोना अभी सस्ता हुआ।

आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, ओमान और सिंगापुर की तुलना में भारत में गोल्ड की कीमत (Gold Price) कम है। ऐसे में गोल्ड की कीमतों में आई गिरावट के पीछे कई कारण हैं पर यह कारण जानने से पहले हम लेटेस्ट



अब कितना सस्ता होगा सोना?

प्राइस (Gold Latest Price) जानते हैं।

क्या है लेटेस्ट प्राइस (Gold Latest Price)

भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 75,650 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 69,350 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इससे दूसरी तरफ 99.9 फीसदी प्योर गोल्ड प्रति 10 ग्राम की कीमत ओमान में 75,763 रुपये और कतर में 76,293 है। इन देशों में भू-राजनीतिक तनावों और मांग के कारण सोने की कीमतों

में तेजी आई है।

क्यों गिर रहा सोने का भाव वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक चिंता

मध्य पूर्व देश यानी इजरायल-गाजा के बीच चल रहे संघर्ष के कारण सोने की कीमत बढ़ गई। दरअसल, भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशक सिक्क्योर एसेट में निवेश करना पसंद करते हैं। हालांकि, इससे जहां कुछ देशों में सोने की कीमतों में तेजी आई, लेकिन भारत में इनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिली।

इंटरनेशनल प्राइस के कारण

ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के हाजिर बाजार में सोने की कीमत 4.5 फीसदी गिरकर 2,563.25 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। यह तीन सालों की सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में कटौती का रुख अपनाया है। ग्लोबल और डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने के कारण सोने की कीमतों में दबाव बढ़ गया है।

भारत में बढ़ी डिमांड वेडिंग सीजन के कारण भारत में सोने की मांग बढ़ गई। इस हफ्ते फिजिकल गोल्ड पर प्रीमियम 16 डॉलर प्रति औंस पहुंच गया। वहीं, पिछले हफ्ते गोल्ड 3 डॉलर प्रति औंस था।

क्या आगे भी गिरगा सोने का भाव

गोल्ड के सस्ते होने पर अब लोगों के मन में सवाल है कि क्या आगे भी इसकी कीमतों में गिरावट आएगी या नहीं। अक्टूबर में गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था, लेकिन इस महीने गोल्ड रिकॉर्ड प्राइस की कीमतों से 7 फीसदी गिर गया है। ऐसे में अगर भू-राजनीतिक तनाव और सेंट्रल बैंक द्वारा खरीदारी जारी रहती है तो गोल्ड की कीमतों स्थिरता आ सकती है।

रिटायरमेंट से पहले जानें कितना मिलेगा पेंशन? यहां समझें पूरा कैलकुलेशन

परिवहन विशेष न्यूज

ईपीएफओ (EPFO) में निवेश के बाद यूजर के मन में सवाल रहता है कि आखिर उन्हें रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन मिलेगा। हम आपको इस आर्टिकल में एक फॉर्मूला बताएंगे जिसके जरिये आप आसानी से पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप 50 साल की उम्र के बाद अर्ली पेंशन का लाभ भी उठा सकते हैं।

नई दिल्ली। रिटायरमेंट के बाद इनकम जारी रहे इसके लिए प्राइवेट जॉब वाले ईपीएफओ (EPFO) में निवेश करते हैं। ईपीएफओ में निवेश के बाद मैच्योरिटी पर एकमुश्त राशि और मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। ईपीएफओ यूजर के मन में एक सवाल बना रहता है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। हम आपको एक फॉर्मूला बताएंगे जिसके जरिये आप आसानी से पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं।

क्या है पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको बता दें कि ईपीएफओ में पेंशन का लाभ तब मिलता है जब आप लगातार 10 साल तक ईपीएफओ में योगदान करते हैं। वहीं, पेंशन के लिए 35 साल तक की सर्विस होनी जरूरी है। पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला (ओसैट सैलरी x पेंशनबल सर्विस/70) है।

● औसत सैलरी में आपको बेसिक



कितनी मिलेगी पेंशन?

सैलरी और महंगाई भत्ता शामिल होता है।

● पेंशनबल सर्विस होती है कि आपने कितने साल जॉब की है।

उदाहरण के तौर पर अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है और 35 साल जॉब करते हैं तो आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करके पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से 15000 x 35 / 70 = 7,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके आप पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं।

पेंशन कैलकुलेट करने का यह फॉर्मूला 15 नवंबर 1995 के बाद संगठित क्षेत्र के कर्मचारी के लिए है। इनसे पहले के कर्मचारी के नियम अलग हैं।

रिटायरमेंट से पहले ले सकते हैं पेंशन

ईपीएफओ अर्ली पेंशन (Early Pension) की भी सुविधा देता है।

वैसे तो 58 साल के बाद यूजर को पेंशन का लाभ मिलता है। 50 साल की उम्र में अर्ली पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट किया जा सकता है। हालांकि, इसमें हर साल 4 फीसदी की कटौती होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप 56 की उम्र में अर्ली पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको 4 फीसदी की कटौती के बाद मूल राशि में 92 फीसदी ही पेंशन के तौर पर मिलेगी।

ईपीएफओ में कितना करना होता है योगदान

ईपीएफओ में हर महीने बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा जमा करना होता है। इसमें कर्मचारी के साथ कंपनी द्वारा भी योगदान किया जाता है। ईपीएफओ फंड में जमा राशि पर सरकार द्वारा ब्याज मिलता है। इस फंड में जमा राशि में रिटायरमेंट के बाद 75 फीसदी एकमुश्त मिलती है और 25 फीसदी पेंशन के तौर पर हर महीने मिलती है।

विदेशी निवेशकों ने अपनाई निकासी की रणनीति, नवंबर में बेचे 22,420 करोड़ रुपये की इक्विटी

नई दिल्ली। अमेरिकी चुनाव के नतीजों के एलान के बाद विदेशी निवेशक (FPI) भारतीय शेयर बाजार से निकासी कर रहे थे। इस निकासी के कारण शेयर बाजार (Share Market) में भारी बिकवाली देखने को मिली। अब नवंबर महीने में एफपीआई आउटफ्लो का डेटा जारी हो गया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार नवंबर में अभी तक विदेशी निवेशकों ने 22,420 करोड़ रुपये तक की इक्विटी बेची। विदेशी निवेशक शेयर बाजार से निकासी करके चीन में निवेश कर रहे हैं। यूएस डॉलर (US Dollar) के मजबूत होने के कारण भी विदेशी निवेशक निकासी कर रहे हैं। नवंबर में हुए आउटफ्लो के बाद एफपीआई (FPI Data November 2024) ने 2024 में कुल 15,827 करोड़ रुपये की निकासी की है।

भारत में फोरेक्स मजार्स के वित्तीय सलाहकार भागीदार अखिल पुरी के अनुसार शेयर बाजार में एफपीआई इनफ्लो थोड़े समय के बाद चालू हो सकती है। जनवरी से पहले एफपीआई इनफ्लो जारी होने की उम्मीद है। अभी एफपीआई आउटफ्लो ने बाजार की चाल को सीमित कर दिया है।

अभी तक कितनी हुई निकासी

एफपीआई डेटा के अनुसार नवंबर में अभी तक विदेशी निवेशकों ने 22,420 करोड़ रुपये की निकासी की है। पिछले महीने में अक्टूबर में 94,017 करोड़ रुपये की निकासी की थी। यह इस साल का अभी तक सबसे ज्यादा आउटफ्लो है। अक्टूबर 2024 से पहले विदेशी निवेशकों ने मार्च 2020 में सबसे ज्यादा निकासी की थी। मार्च 2020 में एफपीआई ने 61,973 करोड़ रुपये विदेशी निकासी की है। सितंबर 2024 में विदेशी निवेशकों ने 57,724 करोड़ रुपये का इनफ्लो किया था, जो 9-महीने का उच्चतम स्तर है।

एफपीआई ने क्या अपनाई आउटफ्लो रणनीति जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार के अनुसार एफपीआई ने अक्टूबर से निकासी की रणनीति तीन कारणों की वजह से अपनाई है। यह तीन वजह- भारत में उच्च वैल्यूएशन, निराशाजनक तिमाही नतीजे और ट्रेंड ट्रेड है।

एफपीआई ने इस समीक्षाधीन अवधि के दौरान डेटा मार्केट में 42 करोड़ रुपये और वीआरआर में 362 करोड़ रुपये का निवेश किया। इस साल अब तक एफपीआई ने डेटा मार्केट में 1.06 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है।

इस हफ्ते भी चार दिन खुलेगा बाजार, निवेशकों को इन फैक्टर्स पर रखना चाहिए नजर

कैसी रहेगी

बाजार की चाल



Market Outlook शेयर बाजार में पिछले हफ्ते 4 दिन ही कारोबार हुआ था। आगामी हफ्ते में भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कारण केवल 4 दिन ही कारोबार होगा। बाजार के दोनों सूचकांक ने सर्कुलर जारी किया है कि 20 नवंबर 2024 को विधानसभा चुनाव के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट ने बताया कि छोटे कारोबारी हफ्तों में निवेशकों को किन फैक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए...

नई दिल्ली। 18 नवंबर से शेयर बाजार का नया कारोबारी हफ्ता शुरू हो जाएगा। इस हफ्ते भी शेयर बाजार में केवल 4 दिन ही ट्रेडिंग होगी। दरअसल, 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में विधान सभा चुनाव के कारण शेयर बाजार में छुट्टी का एलान

किया गया है। इस छोटे कारोबारी हफ्ते में निवेशकों को स्टॉक मार्केट के किन फैक्टर्स पर नजर रखनी होगी?

ये फैक्टर्स रहेंगे अहम

मार्केट एनलिसिस के अनुसार इस हफ्ते भी विदेशी निवेशकों के इनफ्लो और आउटफ्लो पर नजर बनाए रखनी होगी। पिछले हफ्ते विदेशी निवेशकों द्वारा निकासी के कारण बाजार में गिरावट आई थी। एफआईआई के ट्रेडिंग और ग्लोबल ट्रेड्स स्टॉक मार्केट के मुख्य फैक्टर्स हैं।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका चुनावी नतीजों के बाद डॉलर काफी मजबूत हो गया। इन नतीजों का असर भारत जैसे उभरते बाजार पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। पिछले कुछ समय से एफआईआई आउटफ्लो के कारण शेयर बाजार में बिकवाली कारोबार देखने को मिला है। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार

ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेट क्रूड और डॉलर-रुपये के बीच कारोबार का असर भी स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा।

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के एसवीपी, रिसर्च, अजीत मिश्रा ने कहा इस छोटे कारोबारी हफ्तों में निवेशकों की नजर एफआईआई फ्लो पर बनी रहेगी। पिछले डेढ़ महीने से एफआईआई फ्लो का असर शेयर बाजार पर पड़ा है।

सिद्धार्थ खेमका, प्रमुख - अनुसंधान, वेल्थ मैनेजमेंट, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अनुसार निराशाजनक तिमाही नतीजों के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार रहा है। डॉलर के लगातार मजबूत होने और विदेशी निवेशकों द्वारा जारी बिकवाली के कारण पिछले महीने शेयर बाजार के निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा।

